

कार्यालय कार्यपालन अभियंता

लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

Email – ee.surajpur@nic.in

ee.pwdsuraj@gmail.com

Fax No. 07775-266276

क्रमांक / 6258 / तक. / 2025-26

सूरजपुर दिनांक 08 / 02 / 2026

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
सूरजपुर वनमण्डल
जिला सूरजपुर (छ0ग0)

विषय: Diversion of 1.82 ha Forest land in favour of PWD B and R Division Surajpur for Construction of New District Court Building, under Forest Conservation Act, 1980 at Surajpur District, in the State of Chhattisgarh-reg
पंजीयन क्रमांक FP/CG/Others/152258/2022

संदर्भ: भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय अरण्य भवन, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक FC-I/IROCH-15/2022/963 दिनांक 12.10.2022

विषयान्तर्गत संदर्भितपत्रानुसार लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सूरजपुर द्वारा ग्राम तिलसिवां, तहसील सूरजपुर जिला एवं वन वनमण्डल सूरजपुर अन्तर्गत खसरा क्रमांक 529 कुल रकबा 6.394 हे0 में से 1.82 हे0 राजस्व वनभूमि पर नवीन जिला कोर्ट भवन निर्माण के लिए गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय अरण्य भवन द्वारा प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदाय किया गया है। स्वीकृति पत्र के अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है:-

क्रमांक	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
i.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का वैधानिक स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जावेगा, प्रमाण पत्र संलग्न क्र.-01
ii.	Compensatory afforestation	
a)	Compensation afforestation shall be taken up by the Forest Department over 3.64 Ha. Degraded Revenue Forest land in Khasrsa No. 780 at Beat-Premnagar, Range-Ramanujnagar, Village-Bkirma, District Surajpur at the cost of the user agency. As per as possible, a mixture of local indigenous species along with 10% RET species of Surajpur District shall be planted and monoculture of any species may be avoided. At least one water body shall be constructed in the from of Tank/stop	प्रभावित 1.82 हे. राजस्व वन भूमि के एवज में ग्राम बकिरमा, तहसील प्रेमनगर जिला सूरजपुर अन्तर्गत खसरा नंबर 780 कुल रकबा 51.31 हे. भूमि में से दुगन क्षेत्र 3.64 हे. भूमि को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया है। उक्त भूमि पर स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को समायोजित कर नियमानुसार क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण योजना वनमण्डलाधिकारी सूरजपुर वनमण्डल

	dams etc if the same area not available in the area or in nearby vicinity;	द्वारा निर्मित तथा अनुमोदित किया गया है, जिसकी कुल लागत रु. 46,83,399/- का भुगतान ई-चालान के माध्यम से किया गया है प्रमाण पत्र एवं चालान की प्रति संलग्न क्र. -02(अ)
b)	The proposed non-forest CA land shall be transferred and mutated in favour of the State Forest Department before Stage-II Clearance.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित गैर वन वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित करने हेतु न्यायालय कलेक्टर सूरजपुर में आवेदन किया गया है, द्वितीय चरण स्वीकृति पूर्व भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित कर दिया जावेगा, आवेदन की प्रति एवं वचनपत्र संलग्न क्र.- 02(ब)
iii.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey. Demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provisions for anticipated cost escalation for works scheduled for subsequent years;	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित गैर वन क्षेत्र में 10 वर्षीय सिंचित वृक्षारोपण योजना वर्तमान प्रचलित दर पिल्हरो के सीमाकन सहित वन विभाग द्वारा निर्मित किया गया था जिसकी कुल लागत रुपये 46,83,399/- का भुगतान ई-चालान के माध्यम से किया गया है। उक्त योजना लागत में किसी भी प्रकार की वृद्धि होने पर अंतर की राशि के भुगतान हेतु संस्थान वचन बद्ध है वचन पत्र संलग्न क्र.-03
iv.	NPV:	
a)	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 1.82 Ha. Forest area to be diveted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30.10.2002] 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in IA no. 566 in WP (C) no. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letter no. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18.09.2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03.10.2006 and 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard;	नवीन जिला कोर्ट भवन में प्रभावित 1.82 हे0 राजस्व वन भूमि के व्यपवर्तन प्रस्ताव अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार के निदेशों के अनुसार एवं वन विभाग द्वारा प्रत्याषा शुल्क रूपयें 17,43,160/- का गणना पत्रक अनुमोदित किया गया है जिसका भुगतान ई-चालान के माध्यम से संस्थान द्वारा किया गया है, चालान की प्रति संलग्न क्र.-04(अ)
b)	Additional amount of the NPV of the diveted forest land, if nay, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the	व्यपवर्तन प्रस्ताव अंतर्गत विषेषज्ञ समिति द्वारा या माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार के निदेशों के अनुसार एवं वन विभाग द्वारा प्रत्याषा शुल्क की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि की जाती है तो अंतर की राशि के भुगतान हेतु

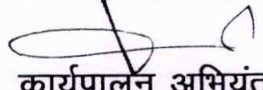
	User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect;	संस्थान वचन बद्ध है, वचन पत्र संलग्न क्र. -04(ब)
v.	No tree felling or cutting shall be permitted under instant proposal;	बिना वैधानिक अनुमति के पूर्व किसी वृक्षो की कटाई आवेदक संस्थान द्वारा नहीं किया जावेगा प्रमाण पत्र संलग्न क्र.-05
vi.	All the funds received from User Agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/);	वन विभाग के निर्देशानुसार व्यपवर्तन प्रस्ताव अंतर्गत सभी प्रकार के भुगतान को ई.पोर्टल के माध्यम से केम्पा फंड में ही किया जावेगा प्रमाण पत्र संलग्न क्र.-06
vii.	The State Government of Chhattisgarh/ Nodel Officer (FCA), Forest Department of Chhattisgarh shall ensure settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007) before issuing order for handing over of forest land to the User Agency as per Rule- 9 (6) (b) (ii) of Forest (Conservation) Rules, 2022 dated 28.06.2022;	व्यपवर्तन प्रस्ताव अंतर्गत आवेदित भूमि पर किसी भी प्रकार का वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 (संख्या 2 एवं 2007) के तहत कोई आबंटन नहीं किया गया है उपरोक्त संबंध ग्राम वन समिति, अनुविभाग स्तरीय वन समिति एवं जिला स्तरीय समिति से प्रस्ताव प्राप्त किया गया है, प्रस्ताव की प्रति प्रमाण पत्र सहित संलग्न क्र.-07
viii.	To improve the Forest/Tree cover and to reduce pollution in the State, as mandated in National Forest Policy, 1988 and Environmental (Protection) Act, 1986 respectively, the User Agency in consultation with local DCF shall raise at least 1500 seedlings of forestry species along with bamboo, fruit bearing, medicinal, ornamental and indigenous/local for 10 years. At least 50% of seedlings shall be planted by User Agency in the vicinity of project area including forest area and for hand holding with local people residing in vicinity of proposed road, A six-monthly compliance report species wise seedlings raised and location of plantation area shall be submitted to Regional Office of MoEF&CC;	नवीन जिला कोर्ट भवन सूरजपुर में प्रभावित 1.82 हे. राजस्व वन भूमि पर भवन क्षेत्र को छोड़कर ग्रीन बैल्ट तैयार किया जाना प्रस्तावित है जिसकी व्यय राशि परियोजना लागत में सम्मिलित है साथ ही मुख्य मार्ग के दोनो किनारों पर भी संस्थान द्वारा वृक्षारोपण वन विभाग के मार्गदर्शन में किया जावेगा तथा समय-समय पर पालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जावेगा, वचन पत्र संलग्न क्र.-08
ix.	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable;	नवीन जिला कोर्ट भवन निर्माण अंतर्गत कोर्ट भवन निर्माण का भू-तल क्षेत्रफल 6355 वर्ग मीटर एवं प्रथम तल का क्षेत्रफल 5154 वर्ग मीटर, द्वितीय तल क्षेत्रफल 1661 वर्ग मीटर कुल निर्माण क्षेत्रफल 13170 वर्ग मीटर निर्धारित है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा

		अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर 2006 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर तक के भवन पर पर्यावरण की स्वीकृति आवश्यक नहीं है, प्रमाण पत्र सहित अधिसूचना की प्रति संलग्न क्र.-09
x.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government;	नवीन जिला कोर्ट भवन निर्माण में प्रस्तावित लेआउट में बिना केन्द्रीय सरकार की अनुमति के पूर्व किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा परियोजना लेआउट प्रमाण पत्र सहित संलग्न क्र.-10
xi.	No labour camp shall be established on the forest land;	व्यपवर्तीत वन भूमि पर किसी भी प्रकार के मजदुरों हेतु निवास का निर्माण नहीं किया जावेगा, प्रमाण पत्र संलग्न क्र.-11
xii.	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel;	नवीन जिला कोर्ट भवन निर्माण में सम्मिलित मजदुरों को ईंधन की व्यवस्था के पर्याप्त साधन वन विभाग या वन विकास निगम से खरीदकर, आवेदक संस्थान द्वारा कराया जावेगा प्रमाण पत्र संलग्न क्र.-12
xiii.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of the concerned Divisional Forest Officer;	नवीन जिला कोर्ट भवन हेतु व्यपवर्तीत 1.82 हे. राजस्व वन भूमि का उचित सीमांकन सीमेंट पिल्हर द्वारा वनमण्डलाधिकारी के निर्देशानुसार किया गया है, प्रमाण पत्र संलग्न क्र.-13
xiv.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work;	नवीन जिला कोर्ट भवन निर्माण हेतु प्रयुक्त सामग्री के परिवहन हेतु वन क्षेत्र अंतर्गत अतिरिक्त मार्ग का निर्माण नहीं किया जावेगा प्रमाण पत्र संलग्न क्र.-14
xv.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less;	नवीन जिला कोर्ट भवन हेतु 1.82 हे. राजस्व वन भूमि का नियमानुसार निर्धारित पट्टे की अवधि से संबंधित सभी निर्देशों का आवेदन संस्थान द्वारा पालन किया जावेगा, प्रमाण पत्र संलग्न क्र.-15
xvi.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal;	उक्त प्रस्ताव में व्यपवर्तीत 1.82 हे. राजस्व वन भूमि का उपयोग केवल नवीन जिला कोर्ट भवन निर्माण हेतु किया जावेगा अन्य किसी उद्देश्य नहीं किया जावेगा प्रमाण पत्र संलग्न क्र.-16
xvii.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India;	नवीन जिला कोर्ट भवन हेतु व्यपवर्तीत 1.82 हे. राजस्व वन भूमि को भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी अन्य संस्थान या विभाग हस्तांतरित नहीं किया जावेगा प्रमाण पत्र संलग्न क्र.-17
xviii.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation)	अधिरोपित किसी भी शर्तों, नियमों एवं निर्देशों का उल्लंघन संस्थान द्वारा नहीं किया जावेगा, प्रमाण

	Act, 1980 and action shall be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt 29/10/2018;	पत्र संलग्न क्र.-18
xix.	Any other condition that the ministry of Environment, Forests & Climate Change may Stipulate from time to time in the intrest of conservation, protection and development of forests & wildlife shall apply;	नवीन जिला कोर्ट भवन व्यपवर्तन प्रस्ताव अंतर्गत वनों और वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा और विकास हेतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली कोई भी अन्य शर्त लागू होगी वह आवेदक संस्थान को मान्य होगी, प्रमाण पत्र संलग्न क्र. -19
xx.	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/);	नवीन जिला कोर्ट भवन व्यपवर्तन प्रस्ताव अंतर्गत अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड किया जावेगा प्रमाण पत्र संलग्न क्र.-20

उपरोक्तानुसार भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय अरण्य भवन, नवा रायपुर के द्वारा अधिरोपित सभी शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रमाण पत्रों एवं वचन पत्रों सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु आपकी ओर सादर प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार संलग्न क्रमांक 01 से 20


कार्यपालन अभियंता
लो0नि0वि0 संभाग सूरजपुर

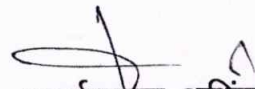
पृ0 क्रमांक.....0259...../तक./2025-26 सूरजपुर

दिनांक 08/03/2026

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग सरगुजा परिक्षेत्र अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. माननीय जिला सत्र न्यायाधीस महोदय सूरजपुर जिला सूरजपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर महोदय सूरजपुर जिला सूरजपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. अधीक्षण अभियंता लो0नि0वि0 अम्बिकापुर मण्डल अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ।

सहपत्र :- शून्य।


कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि.(भ/स) संभाग सूरजपुर

कार्यालय कार्यपालन अभियंता

लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

Email - ee.surajpur@nic.in

ee.pwdsuraj@gmail.com


Fax No. 07775-266276

बिन्दु क्रमांक - 01

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग संभाग सूरजपुर, द्वारा ग्राम तिलसिंवा, तहसील सूरजपुर, जिला एवं वनमण्डल सूरजपुर में प्रस्तावित नवीन जिला कोर्ट भवन निर्माण में प्रभावित 1.82 हे. राजस्व वन भूमि का वैधानिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

दिनांक : 8/03/2026
स्थान : सूरजपुर


कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. संभाग सूरजपुर

कार्यालय कार्यपालन अभियंता

लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

Email - ee.surajpur@nic.in

ee.pwdsuraj@gmail.com


Fax No. 07775-266276

बिन्दु क्रमांक - 02 (अ)

प्रमाण पत्र

लोक निर्माण विभाग संभाग सूरजपुर, द्वारा ग्राम तिलसिंवा, तहसील सूरजपुर, जिला एवं वनमण्डल सूरजपुर अन्तर्गत प्रस्तावित नवीन जिला कोर्ट भवन निर्माण में प्रभावित 1.82 हे. राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव अन्तर्गत ग्राम बकिरमा तहसील प्रेमनगर स्थित खसरा क्रमांक 780 रकबा 3.64 हे. भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयन किया गया है, उक्त भूमि पर स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को समायोजित कर नियमानुसार क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण योजना वनमण्डलाधिकारी सूरजपुर वनमण्डल द्वारा निर्मित तथा अनुमोदित किया गया है, जिसकी कुल लागत रु. 46,83,399/- का भुगतान ई-चालान के माध्यम से किया गया है, चालान की प्रति संलग्न है।

दिनांक : 8/03/2026
स्थान : सूरजपुर


कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. संभाग सूरजपुर

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 27-02-2026

Agency Name.	PWD B AND R DIVISION SURAJPUR
Application No.	199152258485
MoEF/SG File No.	FC-I/ROCH-15/2022
Location.	CHATTISGARH
Address.	PUBLIC WORK DEPARTMENT B/R DIVISION SURAJPUR Surajpur
Amount(in Rs)	6426559/-

Amount in Words :Sixty-Four Lakh Twenty-Six Thousand Five Hundred and Fifty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	CHATTISGARH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	15064199152258485 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 27-02-2026

Agency Name.	PWD B AND R DIVISION SURAJPUR
Application No.	199152258485
MoEF/SG File No.	FC-I/ROCH-15/2022
Location.	CHATTISGARH
Address:	PUBLIC WORK DEPARTMENT B/R DIVISION SURAJPUR Surajpur.
Amount(in Rs)	6426559/-

Amount in Words :Sixty-Four Lakh Twenty-Six Thousand Five Hundred and Fifty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	CHATTISGARH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	15064199152258485 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

SB, Surajpur(00576),C.G.
Pratibha Kumar Paikra PF-7399634
N 27 FEB 2026
Q.No.
अक्षर/नाम (जमा/भुगतान) अन्य हस्ताक्षर

Executive Engineer
W.D.(B/R),Division surajpur
distt.surajpur (C.G.)

SBIN R52026022718376475

कार्यालय कार्यपालन अभियंता

लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

Email - ee.surajpur@nic.in

ee.pwdsuraj@gmail.com


Fax No. 07775-266276

बिन्दु क्रमांक - 02 (ब)

वचन पत्र

लोक निर्माण विभाग संभाग सूरजपुर, द्वारा ग्राम तिलसिंवा, तहसील सूरजपुर, जिला एवं वनमण्डल सूरजपुर अन्तर्गत प्रस्तावित नवीन जिला कोर्ट भवन निर्माण में प्रभावित 1.82 हे. राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव अन्तर्गत ग्राम बकिरमा तहसील प्रेमनगर स्थित खसरा क्रमांक 780 रकबा 3.64 हे. भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उक्त भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित करने हेतु न्यायालय कलेक्टर सूरजपुर में आवेदन किया गया है, द्वितीय चरण स्वीकृति पूर्व भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित कर दिया जावेगा जिस हेतु आवेदक संस्थान वचन बद्ध है, आवेदन की प्रति संलग्न है।

दिनांक : 8/03/2026
स्थान : सूरजपुर


कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. संभाग सूरजपुर

कार्यालय कार्यपालन अभियंता

लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

Email - ee.surajpur@nic.in

ee.pwdsuraj@gmail.com


Fax No. 07775-266276

बिन्दु क्रमांक - 03

वचन पत्र

लोक निर्माण विभाग संभाग सूरजपुर, द्वारा ग्राम तिलसिंवा, तहसील सूरजपुर, जिला एवं वनमण्डल सूरजपुर अन्तर्गत प्रस्तावित नवीन जिला कोर्ट भवन निर्माण में प्रभावित 1.82 हे. राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव अन्तर्गत ग्राम बकिरमा तहसील प्रेमनगर स्थित खसरा क्रमांक 780 रकबा 3.64 हे. भूमि पर क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण योजना तैयार किया गया था, जिसकी कुल लागत रु. 46,83,399/- का भुगतान ई-चालान के माध्यम से किया गया है, उक्त वृक्षारोपण योजना में किसी भी प्रकार की वृद्धि किया जाता है तो अंतर की राशि के भुगतान हेतु संस्थान वचन बद्ध है।

दिनांक : 8/03/2026
स्थान : सूरजपुर


कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. संभाग सूरजपुर

कार्यालय कार्यपालन अभियंता

लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

Email - ee.surajpur@nic.in

ee.pwdsuraj@gmail.com


Fax No. 07775-266276

बिन्दु क्रमांक - 04 (अ)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग संभाग सूरजपुर, द्वारा ग्राम तिलसिंवा, तहसील सूरजपुर, जिला एवं वनमण्डल सूरजपुर अन्तर्गत प्रस्तावित नवीन जिला कोर्ट भवन निर्माण में प्रभावित 1.82 हे. राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव अन्तर्गत वन विभाग द्वारा प्रत्याषा शुल्क रूपये 17,43,160/- राशि का गणना पत्रक अनुमोदित किया गया है जिसका भुगतान ई-चालान के माध्यम से आवेदक संस्थान द्वारा किया गया है, चालान की प्रति संलग्न है।

दिनांक : 8/03/2024
स्थान : सूरजपुर


कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. संभाग सूरजपुर

कार्यालय कार्यपालन अभियंता

लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

Email - ee.surajpur@nic.in

ee.pwdsuraj@gmail.com

Fax No. 07775-266276

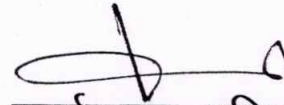
बिन्दु क्रमांक - 04 (ब)

वचन पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग संभाग सूरजपुर, द्वारा ग्राम तिलसिंवा, तहसील सूरजपुर, जिला एवं वनमण्डल सूरजपुर अन्तर्गत प्रस्तावित नवीन जिला कोर्ट भवन निर्माण में प्रभावित 1.82 हे. राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव अन्तर्गत विषेषज्ञ समिति द्वारा या माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार एव वन विभाग द्वारा प्रत्याषा शुल्क में किसी प्रकार की वृद्धि की जाती है तो अंतर की राशि के भुगतान हेतु संस्थान वचन बद्ध है।

दिनांक : 8/3/2026

स्थान : सूरजपुर

कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. संभाग सूरजपुर

कार्यालय कार्यपालन अभियंता

लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

Email - ee.surajpur@nic.in

ee.pwdsuraj@gmail.com

Fax No. 07775-266276


बिन्दु क्रमांक - 05

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग संभाग सूरजपुर, द्वारा ग्राम तिलसिंवा, तहसील सूरजपुर, जिला एवं वनमण्डल सूरजपुर अन्तर्गत प्रस्तावित नवीन जिला कोर्ट भवन निर्माण में प्रभावित 1.82 हे. राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव अन्तर्गत बिना वैधानिक अनुमति के पूर्व किसी भी वृक्षों की कटाई नहीं किया जावेगा।

दिनांक : 8/03/2026

स्थान : सूरजपुर


कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. संभाग सूरजपुर

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 27-02-2026

Agency Name.	PWD B AND R DIVISION SURAJPUR
Application No.	199152258485
MoEF/SG File No.	FC-I/ROCH-15/2022
Location.	CHATTISGARH
Address.	PUBLIC WORK DEPARTMENT B/R DIVISION SURAJPUR Surajpur
Amount(in Rs)	6426559/-

Amount in Words :Sixty-Four Lakh Twenty-Six Thousand Five Hundred and Fifty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	CHATTISGARH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	15064199152258485 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 27-02-2026

Agency Name.	PWD B AND R DIVISION SURAJPUR
Application No.	199152258485
MoEF/SG File No.	FC-I/ROCH-15/2022
Location.	CHATTISGARH
Address:	PUBLIC WORK DEPARTMENT B/R DIVISION SURAJPUR Surajpur
Amount(in Rs)	6426559/-

Amount in Words :Sixty-Four Lakh Twenty-Six Thousand Five Hundred and Fifty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	CHATTISGARH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	15064199152258485 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Sgt, Surajpur(00576), C.G.
Pratul Kumar Painkra PF-7399634
N 27 FEB 2026
Q.No.
अंतरण/नाम/(जमा/भुगतान)अन्य हस्ताक्षर

Executive Engineer
W.D.(B/R), Division surajpur
distt.surajpur (C.G.)

SBIN R52026022718376475

कार्यालय कार्यपालन अभियंता

लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

Email - ee.surajpur@nic.in

ee.pwdsuraj@gmail.com

Fax No. 07775-266276


बिन्दु क्रमांक - 07

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग संभाग सूरजपुर, द्वारा ग्राम तिलसिंवा, तहसील सूरजपुर, जिला एवं वनमण्डल सूरजपुर अन्तर्गत प्रस्तावित नवीन जिला कोर्ट भवन निर्माण में प्रभावित 1.82 हे. राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन व्यपवर्तन प्रस्ताव अंतर्गत आवेदित भूमि पर किसी भी प्रकार का वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 (संख्या 2 एवं 2007) के तहत कोई आबंटन नहीं किया गया है, उपरोक्त संबंध ग्राम वन समिति, अनुविभाग स्तरीय वन समिति एवं जिला स्तरीय समिति से प्रस्ताव प्राप्त किया गया है, प्रस्ताव की प्रति संलग्न है।

दिनांक : 8/03/2026

स्थान : सूरजपुर


कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. संभाग सूरजपुर

कार्यालय कलेक्टर जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

क्रमांक/ 334 /वाचक/2021

सूरजपुर, दिनांक 26/10/2021

:: अनापत्ति प्रमाण पत्र ::

कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (म/स) सभाग सूरजपुर के द्वारा अपने पत्र क्रमांक 7183 तर्क /2020 21 सूरजपुर दिनांक 19/10/2020 के माध्यम से सूरजपुर जिला कोर्ट भवन निर्माण किये जाने हेतु ग्राम तिलसिवा, तहसील सूरजपुर अन्तर्गत स्थित भूमि खसरा नंबर 529 म से रकबा 1.82 हे भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यापारिक वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है।

आवेदक विभाग के आवेदन पर, अनुविभागीय अधिकारी (रा) सूरजपुर से प्रतिवेदन लिया गया। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम-तिलसिवा तहसील-सूरजपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 529 रकबा 6.394 हे वर्तमान राजस्व अभिलेखा में छाट झाड़ के जंगल मद में दर्ज है। उक्त भूमि में से रकबा 1.82 हे भूमि पर जिला कोर्ट भवन निर्माण प्रस्तावित है। वादभूमि का मौका जाच राजस्व एवं वन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। वादभूमि वर्तमान में मौके पर पड़त है। वादभूमि पर किसी प्रकार का कोई पेड़ या झाड़ी जंगल नहीं है। वादभूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत कोई भी व्यक्तिगत सामुदायिक वन अधिकार पत्र आबटित नहीं किया गया है। वादभूमि पर वन निवासियों का कोई मकान नहीं बना हुआ है और न ही इनके द्वारा वादभूमि कृषि कार्य किया जा रहा है। जिससे आवेदक विभाग को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी प्रयोजन की कार्यवाही विधिवत पूर्ण किये जाने हेतु राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जा सकता है।

अतएव ग्राम-तिलसिवा, तहसील-सूरजपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 529 रकबा 6.394 हे में से रकबा 1.82 हे छोटे झाड़ के जंगल मद में दर्ज भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत, नवीन जिला न्यायालय भवन निर्माण अर्थात् गैर वानिकी प्रयोजन हेतु कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, (म/स) सभाग सूरजपुर को उपयोग करने की अनुमति यदि राक्षम विभाग द्वारा प्रदान की जाती है, तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

क्रमांक/334/वाचक/2021
प्रतिलिपि -

- 1 मुख्य वन संरक्षक (भू प्रबंध), कार्यालय मुख्य वन संरक्षक छ.ग अरण्य भवन, मेडिकल कालेज रोड रायपुर, को सूचनार्थ।
- 2 मान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूरजपुर को सादर सूचनार्थ।
- 3 कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, (म/स) सभाग सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4 वनमण्डलाधिकारी सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर

जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

सूरजपुर, दिनांक 26/10/2021

कलेक्टर

जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

FORM-II
(for project other than linear projects)
Government of Chhattisgarh
Office of the District Collector Surajpur

No. 333/Revenue/2021

Dated 20/07/2021


TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted in for non-forest purposes, it is certified that 1.820 hectares of Revenue forest land proposed to be diverted in favour of **Executive Engineer Public Works Dept. (B/R) Division Surajpur for District Court Building in Surajpur** district falls within Jurisdiction of **Tilsiva** village(s) in **Surajpur** tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.820 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) are enclosed as annexure 01 to annexure 11.
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular / local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA,
- (c) The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities / processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of **Tilsiva** village(s) is enclosed as annexure 01 to annexure 09 .
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and Gram Sabhas have given their consent to it;
- (f) The Rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA. Proposal do not have such groups.

Encl.: As above.


(Dr. Gaurav Kumar Singh)
Collector
DIST. - SURAJPUR

ग्राम सभा तिलसिवां की बैठक दिनांक 23/03/2024

का कार्यवाही विवरण

नाम तिलसिवां

स्थान पंचायत शान

दिनांक

आज दिनांक 23/03/2024 को ग्राम तिलसिवां के सरपंच श्री/श्रीमती

की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के ...

08 सदस्य 92 प्रतिशत उपस्थित थे; बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:-

1. ग्राम तिलसिवां में आवेदक जिला एवं ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि का उपयोग हेतु 1.820 हे. वन भूमि 1.820 हे. राजस्व वन भूमि, कुल 1.820 हे. वन भूमि की प्रस्तावित की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।

2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग के संबंध में ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।

3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिदृश्य में अनुसूचित जंगल जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि जिला एवं राज्य शासनालय कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, न कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रस्तावित वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया


गया है:

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
—	—	—	—

उक्त: यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 1.820 हे. वन भूमि / 1.820 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 1.820 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स

(आवेदक) जिला एवं शासनालय को अन्य प्राचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।


सचिव
ग्राम पंचायत तिलसिवां
ज.पं.+जिला-सूरजपुर (उ.प्र.)


हरताक्षर सरपंच
नाम ग्राम पंचायत तिलसिवां
ज.पं.+जिला-सूरजपुर (उ.प्र.)
सरपंच

सील

उपस्थित सदस्य वगैरे:

संख्या

दिनांक

ग्राम सभा

ग्राम सभा के

कार्यवाही पंजी

कार्यवाही अधिनियम

1. ग्राम पंचायत का नाम निंदन सिवली
2. सम्मिलन का स्थान पंचायत कक्ष

अनुक्रमांक (1)

ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय (2)

3. उपस्थित ग्राम सदस्यों की संख्या 33
4. सम्मिलन की तारीख 2023/03/19 स्थितिस्थान का समय 12.00

सम्मिलन के कार्यक्रम

<p>प्रस्ताव क्र. 03</p> <p>इसे बिलियन के तहत एक कुल कुल योजना लागू करने के लिए ग्राम सभा की अध्यक्षता में एक बैठक के आयोजन के लिए प्रस्तावित किया गया है।</p>	<p>ग्राम सभा बैठक में 14.03.2023 को आयोजित बैठक में ग्राम सभा के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव पर चर्चा के बाद ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या 33 थी।</p>
<p>प्रस्ताव क्र. 04</p> <p>ग्राम सभा के तहत एक कुल कुल योजना लागू करने के लिए ग्राम सभा की अध्यक्षता में एक बैठक के आयोजन के लिए प्रस्तावित किया गया है।</p>	<p>ग्राम सभा बैठक में 14.03.2023 को आयोजित बैठक में ग्राम सभा के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव पर चर्चा के बाद ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या 33 थी।</p>
<p>प्रस्ताव क्र. 05</p> <p>ग्राम सभा के तहत एक कुल कुल योजना लागू करने के लिए ग्राम सभा की अध्यक्षता में एक बैठक के आयोजन के लिए प्रस्तावित किया गया है।</p>	<p>ग्राम सभा बैठक में 14.03.2023 को आयोजित बैठक में ग्राम सभा के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव पर चर्चा के बाद ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या 33 थी।</p>

ग्राम पंचायत
अध्यक्ष/सचिव का स्थान

(Signature)

ग्राम सभा के अध्यक्ष के स्थान पर

तारीख:

ग्राम सभा तिलसिवा की बैठक दिनांक 05/07/2021 का कार्यवाही विवरण

ग्राम: तिलसिवा
स्थान: पंचायत गवन
दिनांक: 05/07/2021 का ग्राम तिलसिवा का सरपंच श्री/श्रीमती कुमेश्वर

विह की आयुक्ता ने ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के 512 का अनुसूचित प्रारिथत में बैठक में निम्न विषय पर चर्चा का कार्य:-

1. ग्राम तिलसिवा में आवक जिला एवं सत्र न्यायालय ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि का विवरण है 1.820 हे. वन भूमि 1.820 हे. सम्बन्ध वन भूमि, कुल 1.820 हे. वन भूमि की परम्परागत बाबट विस्तृत चर्चा की गयी।

2. प्रस्ताव के तहत उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग के लिए ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से महान चर्चा की गयी।

3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिपेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि जिला एवं सत्र न्यायालय कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, वे कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रकार की वन भूमि पर कृषि कार्य, प्रायम के अन्य आवधिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है

क्र	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)

ग्राम तिलसिवा में ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 1.820 हे. वन भूमि / 1.820 हे. सम्बन्ध वन भूमि, कुल योग 1.820 हे. वन भूमि का वन अधिकार प्रस्ताव हेतु भारत सरकार के उक्त प्रस्तावित नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

(आयुक्त) जिला एवं सत्र न्यायालय

शिव प्रताप सिंह
0884588
ग्राम सभा
सचिव
ग्राम पंचायत तिलसिवा
ज.प.+जिला-भूखपुर (उ.ग.)

हस्ताक्षर
नाम: कुमेश्वर
सरपंच
श्रीलाल
तिलसिवा
ज.प.+जिला-भूखपुर (उ.ग.)

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक- 04/06/2021
का कार्यवाही विवरण

स्थान: सूरजपुर

दिनांक- 04/06/2021

आज दिनांक 04/06/2021 को अनुविभागीय अधिकारी (रा) सूरजपुर की अध्यक्षता में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:-

1. ग्राम तिलसिवा में कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सूरजपुर के द्वारा सूरजपुर जिला कोर्ट भवन निर्माण हेतु खसरा नम्बर 529 में से रकबा 1.820 हे. भूमि चयनित किया गया है। उक्त भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन किया जाना है। इस बाबद ग्राम स्तरीय समिति से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव बाबद विस्तृत चर्चा की गयी। प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-


क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	हल्का नम्बर	खसरा नम्बर	रकबा हे. में	जिला कोर्ट भवन निर्माण हेतु प्रभावित रकबा	मद्	FRA के तहत जारी वन अधिकार की मान्यता पत्र
1	तिलसिवा	07	529	6.394 हे.	1.820 हे.	छोटे झाड़ के जंगल (राजस्व वन भूमि)	निरंक

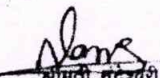
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबद उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।

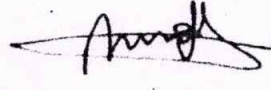
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। ग्राम तिलसिवा स्थित राजस्व वन भूमि खसरा नम्बर 529 में से रकबा 1.820 हे. भूमि सूरजपुर जिला कोर्ट भवन निर्माण हेतु कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नावली वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारस्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासियों को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।


अतः यह एकमत से उपखण्ड स्तरीय समिति में निर्णय लिया गया कि ग्राम तिलसिवा स्थित राजस्व वन भूमि खसरा नम्बर 529 में से रकबा 1.820 हे. भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सूरजपुर के द्वारा उक्त भूमि पर सूरजपुर जिला कोर्ट भवन निर्माण हेतु अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

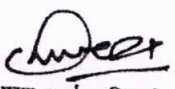
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार
समिति सूरजपुर


अनुविभागीय अधिकारी (वन)
सदस्य, उपखण्ड स्तरीय वन
अधिकार समिति


श्रीमती नंदशेरी
सदस्य, उपखण्ड स्तरीय वन
अधिकार समिति


श्री अमर सिंह
सदस्य, उपखण्ड स्तरीय वन
अधिकार समिति


श्री तुलसी राम यादव
सदस्य, उपखण्ड स्तरीय वन
अधिकार समिति


मुख्य कार्य, अधिकारी
सदस्य, उपखण्ड स्तरीय वन
अधिकार समिति

कार्यालय कार्यपालन अभियंता

लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

Email - ee.surajpur@nic.in

ee.pwdsuraj@gmail.com


Fax No. 07775-266276

बिन्दु क्रमांक - 08

वचन पत्र

लोक निर्माण विभाग संभाग सूरजपुर, द्वारा ग्राम तिलसिंवा, तहसील सूरजपुर, जिला एवं वनमण्डल सूरजपुर अन्तर्गत प्रस्तावित नवीन जिला कोर्ट भवन निर्माण में प्रभावित 1.82 हे. राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन व्यपवर्तन प्रस्ताव अंतर्गत भवन क्षेत्र को छोड़कर ग्रीन बेल्ट तैयार किया जाना प्रस्तावित है जिसकी व्यय राशि परियोजना लागत में सम्मिलित है साथ ही मुख्य मार्ग के दोनो किनारों पर भी संस्थान द्वारा वृक्षारोपण वन विभाग के मार्गदर्शन में किया जावेगा तथा समय-समय पर पालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जावेगा जिस हेतु संस्थान वचन बद्ध है।

दिनांक : 8/03/2021
स्थान : सूरजपुर


कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. संभाग सूरजपुर

कार्यालय कार्यपालन अभियंता

लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

Email - ee.surajpur@nic.in

ee.pwdsuraj@gmail.com


Fax No. 07775-266276

बिन्दु क्रमांक - 09

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग, संभाग सूरजपुर द्वारा प्रस्तावित नवीन जिला कोर्ट भवन निर्माण में प्रभावित 1.82 हे. राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव हेतु पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं हैं। प्रस्तावित भवन भू-तल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल का कुल निर्माण क्षेत्रफल 13170 वर्ग मीटर है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर 2006 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर तक के भवन परियोजना पर पर्यावरण की स्वीकृति आवश्यक नहीं है, अधिसूचना की प्रति संलग्न है।

दिनांक : 8/03/2026
स्थान : सूरजपुर


कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. संभाग सूरजपुर

(Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, and Section 3, Sub-section (ii)
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi 14th September, 2006

Notification

S.O. 1533 Whereas, a draft notification **under sub-rule (3) of Rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for imposing** certain restrictions and prohibitions on new projects or activities, or on the expansion or modernization of existing projects or activities based on their potential environmental impacts as indicated in the Schedule to the notification, being undertaken in any part of India¹, unless prior environmental clearance has been accorded in accordance with the objectives of National Environment Policy as **approved by the Union Cabinet on 18th May, 2006** and the procedure specified in the notification, by the Central Government or the State or Union territory Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), to be constituted by the Central Government in consultation with the State Government or the Union territory Administration concerned under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 for the purpose of this notification, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 1324 (E) dated the 15th September, 2005 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 15th September, 2005;

And whereas, all objections and suggestions received in response to the above mentioned draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 and in supersession of the notification number S.O. 60 (E) dated the 27th January, 1994, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that on and from the date of its publication the required construction of new projects or activities or the expansion or modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to this notification entailing capacity addition with change in process and or technology shall be undertaken in any part of India only after the prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State Level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the said Act, in accordance with the procedure specified hereinafter in this notification.

¹Includes the territorial waters

2. Requirements of prior Environmental Clearance (EC):- The following projects or activities shall require prior environmental clearance from the concerned regulatory authority, which shall hereinafter referred to be as the Central Government in the Ministry of Environment and Forests for matters falling under Category 'A' in the Schedule and at State level the State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) for matters falling under Category 'B' in the said Schedule, before any construction work, or preparation of land by the project management except for securing the land, is started on the project or activity:

- (i) All new projects or activities listed in the Schedule to this notification;
- (ii) Expansion and modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to this notification with addition of capacity beyond the limits specified for the concerned sector, that is, projects or activities which cross the threshold limits given in the Schedule, after expansion or modernization;
- (iii) Any change in product - mix in an existing manufacturing unit included in Schedule beyond the specified range.

3. State Level Environment Impact Assessment Authority:- (1) A State Level Environment Impact Assessment Authority hereinafter referred to as the SEIAA shall be constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of three Members including a Chairman and a Member – Secretary to be nominated by the State Government or the Union territory Administration concerned.

- (2) The Member-Secretary shall be a serving officer of the concerned State Government or Union territory administration familiar with environmental laws.
- (3) The other two Members shall be either a professional or expert fulfilling the eligibility criteria given in Appendix VI to this notification.
- (4) One of the specified Members in sub-paragraph (3) above who is an expert in the Environmental Impact Assessment process shall be the Chairman of the SEIAA.
- (5) The State Government or Union territory Administration shall forward the names of the Members and the Chairman referred in sub- paragraph 3 to 4 above to the Central Government and the Central Government shall constitute the SEIAA as an authority for the purposes of this notification within thirty days of the date of receipt of the names.
- (6) The non-official Member and the Chairman shall have a fixed term of three years (from the date of the publication of the notification by the Central Government constituting the authority).
- (7) All decisions of the SEIAA shall be unanimous and taken in a meeting.

4. Categorization of projects and activities:-

- (i) All projects and activities are broadly categorized in to two categories - Category A and Category B, based on the spatial extent of potential impacts and potential impacts on human health and natural and man made resources.

(ii) All projects or activities included as Category 'A' in the Schedule, including expansion and modernization of existing projects or activities and change in product mix, shall require prior environmental clearance from the Central Government in the Ministry of Environment and Forests (MoEF) on the recommendations of an Expert Appraisal Committee (EAC) to be constituted by the Central Government for the purposes of this notification;

(iii) All projects or activities included as Category 'B' in the Schedule, including expansion and modernization of existing projects or activities as specified in sub paragraph (ii) of paragraph 2, or change in product mix as specified in sub paragraph (iii) of paragraph 2, but excluding those which fulfill the General Conditions (GC) stipulated in the Schedule, *will* require prior environmental clearance from the State/Union territory Environment Impact Assessment Authority (SEIAA). The SEIAA shall base its decision on the recommendations of a State or Union territory level Expert Appraisal Committee (SEAC) as to be constituted for in this notification. In the absence of a duly constituted SEIAA or SEAC, a Category 'B' project shall be treated as a Category 'A' project;

5. Screening, Scoping and Appraisal Committees:-

The same Expert Appraisal Committees (EACs) at the Central Government and SEACs (hereinafter referred to as the (EAC) and (SEAC) at the State or the Union territory level shall screen, scope and appraise projects or activities in Category 'A' and Category 'B' respectively. EAC and SEAC's shall meet at least once every month.

(a) The composition of the EAC shall be as given in Appendix VI. The SEAC at the State or the Union territory level shall be constituted by the Central Government in consultation with the concerned State Government or the Union territory Administration with identical composition;

(b) The Central Government may, with the prior concurrence of the concerned State Governments or the Union territory Administrations, constitute one SEAC for more than one State or Union territory for reasons of administrative convenience and cost;

(c) The EAC and SEAC shall be reconstituted after every three years;

(d) The authorised members of the EAC and SEAC, concerned, may inspect any site(s) connected with the project or activity in respect of which the prior environmental clearance is sought, for the purposes of screening or scoping or appraisal, with prior notice of at least seven days to the applicant, who shall provide necessary facilities for the inspection;

(e) The EAC and SEACs shall function on the principle of collective responsibility. The Chairperson shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

6. Application for Prior Environmental Clearance (EC):-

An application seeking prior environmental clearance in all cases shall be made in the prescribed Form 1 annexed herewith and Supplementary Form 1A, if applicable, as given in Appendix II, after the identification of prospective site(s) for the project and/or activities to which the application relates, before commencing any construction activity, or preparation of land, at the site by the applicant. The applicant shall furnish, along with the application, a copy of the pre-feasibility project report except that, in case of construction projects or activities (item 8 of the Schedule) in addition to Form 1 and the Supplementary Form 1A, a copy of the conceptual plan shall be provided, instead of the pre-feasibility report.

7. Stages in the Prior Environmental Clearance (EC) Process for New Projects:-

7(i) The environmental clearance process for new projects will comprise of a maximum of four stages, all of which may not apply to particular cases as set forth below in this notification. These four stages in sequential order are:-

- Stage (1) Screening (Only for Category 'B' projects and activities)
- Stage (2) Scoping
- Stage (3) Public Consultation
- Stage (4) Appraisal

I. Stage (1) - Screening:

In case of Category 'B' projects or activities, this stage will entail the scrutiny of an application seeking prior environmental clearance made in Form 1 by the concerned State level Expert Appraisal Committee (SEAC) for determining whether or not the project or activity requires further environmental studies for preparation of an Environmental Impact Assessment (EIA) for its appraisal prior to the grant of environmental clearance depending up on the nature and location specificity of the project . The projects requiring an Environmental Impact Assessment report shall be termed Category 'B1' and remaining projects shall be termed Category 'B2' and will not require an Environment Impact Assessment report. For categorization of projects into B1 or B2 except item 8 (b), the Ministry of Environment and Forests shall issue appropriate guidelines from time to time.

II. Stage (2) - Scoping:

(i) "Scoping": refers to the process by which the Expert Appraisal Committee in the case of Category 'A' projects or activities, and State level Expert Appraisal Committee in the case of Category 'B1' projects or activities, including applications for expansion and/or modernization and/or change in product mix of existing projects or activities, determine detailed and comprehensive Terms Of Reference (TOR) addressing all relevant environmental concerns for the preparation of an Environment Impact Assessment (EIA) Report in respect of the project or activity for which prior environmental clearance is sought. The Expert Appraisal Committee or State level Expert Appraisal Committee concerned shall determine the Terms of Reference on the basis of the information furnished in the prescribed application Form1/Form 1A including Terms of Reference proposed by the applicant, a site visit by a sub- group of Expert Appraisal Committee or State level Expert Appraisal Committee concerned only if considered necessary by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned, Terms of Reference suggested by the applicant if furnished and other information that may be available with the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned. All projects and activities listed as Category 'B' in Item 8 of the Schedule (Construction/Township/Commercial Complexes /Housing) shall not require Scoping and will be appraised on the basis of Form 1/ Form 1A and the conceptual plan.

(ii) The Terms of Reference (TOR) shall be conveyed to the applicant by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee as concerned within sixty days of the receipt of Form 1. In the case of Category A Hydroelectric projects Item 1(c) (i) of the Schedule the Terms of Reference shall be conveyed along with the clearance for pre-construction activities .If the Terms of Reference are not finalized and conveyed to the applicant within sixty days of the receipt of Form 1, the Terms of Reference suggested by the applicant shall be deemed as the final Terms of Reference approved for the EIA studies. The approved Terms of

Reference shall be displayed on the website of the Ministry of Environment and Forests and the concerned State Level Environment Impact Assessment Authority.

(iii) Applications for prior environmental clearance may be rejected by the regulatory authority concerned on the recommendation of the EAC or SEAC concerned at this stage itself. In case of such rejection, the decision together with reasons for the same shall be communicated to the applicant in writing within sixty days of the receipt of the application.

III. Stage (3) - Public Consultation:

(i) "Public Consultation" refers to the process by which the concerns of local affected persons and others who have plausible stake in the environmental impacts of the project or activity are ascertained with a view to taking into account all the material concerns in the project or activity design as appropriate. All Category 'A' and Category B1 projects or activities shall undertake Public Consultation, except the following:-

- (a) modernization of irrigation projects (item 1(c) (ii) of the Schedule).
- (b) all projects or activities located within industrial estates or parks (item 7(c) of the Schedule) approved by the concerned authorities, and which are not disallowed in such approvals.
- (c) expansion of Roads and Highways (item 7 (f) of the Schedule) which do not involve any further acquisition of land.
- (d) all Building /Construction projects/Area Development projects and Townships (item 8).
- (e) all Category 'B2' projects and activities.
- (f) all projects or activities concerning national defence and security or involving other strategic considerations as determined by the Central Government.

(ii) The Public Consultation shall ordinarily have two components comprising of:-

(a) a public hearing at the site or in its close proximity- district wise, to be carried out in the manner prescribed in Appendix IV, for ascertaining concerns of local affected persons;

(b) obtain responses in writing from other concerned persons having a plausible stake in the environmental aspects of the project or activity.

(iii) the public hearing at, or in close proximity to, the site(s) in all cases shall be conducted by the State Pollution Control Board (SPCB) or the Union territory Pollution Control Committee (UTPCC) concerned in the specified manner and forward the proceedings to the regulatory authority concerned within 45(forty five) of a request to the effect from the applicant.

(iv) in case the State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee concerned does not undertake and complete the public hearing within the specified period, and/or does not convey the proceedings of the public hearing within the prescribed period

directly to the regulatory authority concerned as above, the regulatory authority shall engage another public agency or authority which is not subordinate to the regulatory authority, to complete the process within a further period of forty five days,.

(v) If the public agency or authority nominated under the sub paragraph (iii) above reports to the regulatory authority concerned that owing to the local situation, it is not possible to conduct the public hearing in a manner which will enable the views of the concerned local persons to be freely expressed, it shall report the facts in detail to the concerned regulatory authority, which may, after due consideration of the report and other reliable information that it may have, decide that the public consultation in the case need not include the public hearing.

(vi) For obtaining responses in writing from other concerned persons having a plausible stake in the environmental aspects of the project or activity, the concerned regulatory authority and the State Pollution Control Board (SPCB) or the Union territory Pollution Control Committee (UTPCC) shall invite responses from such concerned persons by placing on their website the Summary EIA report prepared in the format given in Appendix IIIA by the applicant along with a copy of the application in the prescribed form , within seven days of the receipt of a written request for arranging the public hearing . Confidential information including non-disclosable or legally privileged information involving Intellectual Property Right, source specified in the application shall not be placed on the web site. The regulatory authority concerned may also use other appropriate media for ensuring wide publicity about the project or activity. The regulatory authority shall, however, make available on a written request from any concerned person the Draft EIA report for inspection at a notified place during normal office hours till the date of the public hearing. All the responses received as part of this public consultation process shall be forwarded to the applicant through the quickest available means.

(vii) After completion of the public consultation, the applicant shall address all the material environmental concerns expressed during this process, and make appropriate changes in the draft EIA and EMP. The final EIA report, so prepared, shall be submitted by the applicant to the concerned regulatory authority for appraisal. The applicant may alternatively submit a supplementary report to draft EIA and EMP addressing all the concerns expressed during the public consultation.

IV. Stage (4) - Appraisal:

(i) Appraisal means the detailed scrutiny by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee of the application and other documents like the Final EIA report, outcome of the public consultations including public hearing proceedings, submitted by the applicant to the regulatory authority concerned for grant of environmental clearance. This appraisal shall be made by Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned in a transparent manner in a proceeding to which the applicant shall be invited for furnishing necessary clarifications in person or through an authorized representative. On conclusion of this proceeding, the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned shall make categorical recommendations to the regulatory authority concerned either for grant of prior environmental clearance on stipulated terms and conditions, or rejection of the application for prior environmental clearance, together with reasons for the same.

(ii) The appraisal of all projects or activities which are not required to undergo public consultation, or submit an Environment Impact Assessment report, shall be carried out on the basis of the prescribed application Form 1 and Form 1A as applicable, any other relevant

validated information available and the site visit wherever the same is considered as necessary by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned.

(iii) The appraisal of an application shall be completed by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned within sixty days of the receipt of the final Environment Impact Assessment report and other documents or the receipt of Form 1 and Form 1 A, where public consultation is not necessary and the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee shall be placed before the competent authority for a final decision within the next fifteen days. The prescribed procedure for appraisal is given in Appendix V ;

7(ii). Prior Environmental Clearance (EC) process for Expansion or Modernization or Change of product mix in existing projects:

All applications seeking prior environmental clearance for expansion with increase in the production capacity beyond the capacity for which prior environmental clearance has been granted under this notification or with increase in either lease area or production capacity in the case of mining projects or for the modernization of an existing unit with increase in the total production capacity beyond the threshold limit prescribed in the Schedule to this notification through change in process and or technology or involving a change in the product –mix shall be made in Form I and they shall be considered by the concerned Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee within sixty days, who will decide on the due diligence necessary including preparation of EIA and public consultations and the application shall be appraised accordingly for grant of environmental clearance.

8. Grant or Rejection of Prior Environmental Clearance (EC):

(i) The regulatory authority shall consider the recommendations of the EAC or SEAC concerned and convey its decision to the applicant within forty five days of the receipt of the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned or in other words within one hundred and five days of the receipt of the final Environment Impact Assessment Report, and where Environment Impact Assessment is not required, within one hundred and five days of the receipt of the complete application with requisite documents, except as provided below.

(ii) The regulatory authority shall normally accept the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned. In cases where it disagrees with the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned, the regulatory authority shall request reconsideration by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned within forty five days of the receipt of the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned while stating the reasons for the disagreement. An intimation of this decision shall be simultaneously conveyed to the applicant. The Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned, in turn, shall consider the observations of the regulatory authority and furnish its views on the same within a further period of sixty days. The decision of the regulatory authority after considering the views of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned shall be final and conveyed to the applicant by the regulatory authority concerned within the next thirty days.

(iii) In the event that the decision of the regulatory authority is not communicated to the applicant within the period specified in sub-paragraphs (i) or (ii) above, as applicable, the

applicant may proceed as if the environment clearance sought for has been granted or denied by the regulatory authority in terms of the final recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned.

(iv) On expiry of the period specified for decision by the regulatory authority under paragraph (i) and (ii) above, as applicable, the decision of the regulatory authority, and the final recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned shall be public documents.

(v) Clearances from other regulatory bodies or authorities shall not be required prior to receipt of applications for prior environmental clearance of projects or activities, or screening, or scoping, or appraisal, or decision by the regulatory authority concerned, unless any of these is sequentially dependent on such clearance either due to a requirement of law, or for necessary technical reasons.

(vi) Deliberate concealment and/or submission of false or misleading information or data which is material to screening or scoping or appraisal or decision on the application shall make the application liable for rejection, and cancellation of prior environmental clearance granted on that basis. Rejection of an application or cancellation of a prior environmental clearance already granted, on such ground, shall be decided by the regulatory authority, after giving a personal hearing to the applicant, and following the principles of natural justice.

9. Validity of Environmental Clearance (EC):

The "Validity of Environmental Clearance" is meant the period from which a prior environmental clearance is granted by the regulatory authority, or may be presumed by the applicant to have been granted under sub paragraph (iv) of paragraph 7 above, to the start of production operations by the project or activity, or completion of all construction operations in case of construction projects (item 8 of the Schedule), to which the application for prior environmental clearance refers. The prior environmental clearance granted for a project or activity shall be valid for a period of ten years in the case of River Valley projects (item 1(c) of the Schedule), project life as estimated by Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee subject to a maximum of thirty years for mining projects and five years in the case of all other projects and activities. However, in the case of Area Development projects and Townships [item 8(b)], the validity period shall be limited only to such activities as may be the responsibility of the applicant as a developer. This period of validity may be extended by the regulatory authority concerned by a maximum period of five years provided an application is made to the regulatory authority by the applicant within the validity period, together with an updated Form 1, and Supplementary Form 1A, for Construction projects or activities (item 8 of the Schedule). In this regard the regulatory authority may also consult the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee as the case may be.

10. Post Environmental Clearance Monitoring:

(i) It shall be mandatory for the project management to submit half-yearly compliance reports in respect of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions in hard and soft copies to the regulatory authority concerned, on 1st June and 1st December of each calendar year.

(ii) All such compliance reports submitted by the project management shall be public documents. Copies of the same shall be given to any person on application to the concerned regulatory authority. The latest such compliance report shall also be displayed on the web site of the concerned regulatory authority.

11. Transferability of Environmental Clearance (EC):

A prior environmental clearance granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application by the transferor, or by the transferee with a written "no objection" by the transferor, to, and by the regulatory authority concerned, on the same terms and conditions under which the prior environmental clearance was initially granted, and for the same validity period. No reference to the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned is necessary in such cases.

12. Operation of EIA Notification, 1994, till disposal of pending cases:

From the date of final publication of this notification the Environment Impact Assessment (EIA) notification number S.O.60 (E) dated 27th January, 1994 is hereby superseded, except in suppression of the things done or omitted to be done before such suppression to the extent that in case of all or some types of applications made for prior environmental clearance and pending on the date of final publication of this notification, the Central Government may relax any one or all provisions of this notification except the list of the projects or activities requiring prior environmental clearance in Schedule I, or continue operation of some or all provisions of the said notification, for a period not exceeding one year from the date of issue of this notification.

[No. J-11013/56/2004-IA-II (I)]

(R.CHANDRAMOHAN)
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

SCHEDULE

(See paragraph 2 and 7)

LIST OF PROJECTS OR ACTIVITIES REQUIRING PRIOR ENVIRONMENTAL CLEARANCE

Project or Activity		Category with threshold limit		Conditions if any
		A	B	
1		Mining, extraction of natural resources and power generation (for a specified production capacity)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1(a)	Mining of minerals	<p>≥ 50 ha. of mining lease area</p> <p>Asbestos mining irrespective of mining area</p>	<p><50 ha</p> <p>≥ 5 ha .of mining lease area.</p>	<p>General Condition shall apply</p> <p><u>Note</u></p> <p>Mineral prospecting (not involving drilling) are exempted provided the concession areas have got previous clearance for physical survey</p>
1(b)	Offshore and onshore oil and gas exploration, development & production	All projects		<p><u>Note</u></p> <p>Exploration Surveys (not involving drilling) are exempted provided the concession areas have got previous clearance for physical survey</p>
1(c)	River Valley projects	<p>(i) ≥ 50 MW hydroelectric power generation;</p> <p>(ii) ≥ 10,000 ha. of culturable command area</p>	<p>(i) < 50 MW ≥ 25 MW hydroelectric power generation;</p> <p>(ii) < 10,000 ha. of culturable command area</p>	General Condition shall apply
1(d)	Thermal Power Plants	<p>≥ 500 MW (coal/lignite/naptha & gas based);</p> <p>≥ 50 MW (Pet coke diesel and all other fuels -)</p>	<p>< 500 MW (coal/lignite/naptha & gas based);</p> <p><50 MW</p> <p>≥ 5MW (Pet coke ,diesel and all other fuels)</p>	General Condition shall apply

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1(e)	Nuclear power projects and processing of nuclear fuel	All projects	-	
2		Primary Processing		
2(a)	Coal washeries	≥ 1 million ton/annum throughput of coal	<1million ton/annum throughput of coal	General Condition shall apply (If located within mining area the proposal shall be appraised together with the mining proposal)
2 (b)	Mineral beneficiation	≥ 0.1million ton/annum mineral throughput	< 0.1million ton/annum mineral throughput	General Condition shall apply (Mining proposal with Mineral beneficiation shall be appraised together for grant of clearance)

3				
Materials Production				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3(a)	Metallurgical industries (ferrous & non ferrous)	<p>a) Primary metallurgical industry</p> <p>All projects</p> <p>b) Sponge iron manufacturing ≥ 200TPD</p> <p>c) Secondary metallurgical processing industry</p> <p>All toxic and heavy metal producing units $\geq 20,000$ tonnes /annum</p> <p>-</p>	<p>Sponge iron manufacturing <200TPD</p> <p>Secondary metallurgical processing industry</p> <p>i.) All toxic and heavy metal producing units <20,000 tonnes /annum</p> <p>ii.) All other non-toxic secondary metallurgical processing industries >5000 tonnes/annum</p>	General Condition shall apply for Sponge iron manufacturing
3(b)	Cement plants	≥ 1.0 million tonnes/annum production capacity	<1.0 million tonnes/annum production capacity. All Stand alone grinding units	General Condition shall apply

4				
Materials Processing				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4(a)	Petroleum refining industry	All projects	-	-
4(b)	Coke oven plants	≥2,50,000 tonnes/annum	<2,50,000 & ≥25,000 tonnes/annum	-
4(c)	Asbestos milling and asbestos based products	All projects	-	-
4(d)	Chlor-alkali industry	≥300 TPD production capacity or a unit located out side the notified industrial area/estate	<300 TPD production capacity and located within a notified industrial area/estate	Specific Condition shall apply No new Mercury Cell based plants will be permitted and existing units converting to membrane cell technology are exempted from this Notification
4(e)	Soda ash Industry	All projects	-	-
4(f)	Leather/skin/hide processing industry	New projects outside the industrial area or expansion of existing units out side the industrial area	All new or expansion of projects located within a notified industrial area/estate	Specific condition shall apply
5				
Manufacturing/Fabrication				
5(a)	Chemical fertilizers	All projects	-	-
5(b)	Pesticides industry and pesticide specific intermediates (excluding formulations)	All units producing technical grade pesticides	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5(c)	Petro-chemical complexes (industries based on processing of petroleum fractions & natural gas and/or reforming to aromatics)	All projects -	-	-
5(d)	Manmade fibres manufacturing	Rayon	Others	General Condition shall apply
5(e)	Petrochemical based processing (processes other than cracking & reformation and not covered under the complexes)	Located out side the notified industrial area/ estate -	Located in a notified industrial area/ estate	Specific Condition shall apply
5(f)	Synthetic organic chemicals industry (dyes & dye intermediates; bulk drugs and intermediates excluding drug formulations; synthetic rubbers; basic organic chemicals, other synthetic organic chemicals and chemical intermediates)	Located out side the notified industrial area/ estate	Located in a notified industrial area/ estate	Specific Condition shall apply
5(g)	Distilleries	(i) All Molasses based distilleries (ii) All Cane juice/ non-molasses based distilleries ≥ 30 KLD	All Cane juice/non-molasses based distilleries - <30 KLD	General Condition shall apply
5(h)	Integrated paint industry	-	All projects	General Condition shall apply

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5(i)	Pulp & paper industry excluding manufacturing of paper from waste paper and manufacture of paper from ready pulp with out bleaching	Pulp manufacturing and Pulp& Paper manufacturing industry -	Paper manufacturing industry without pulp manufacturing	General Condition shall apply
5(j)	Sugar Industry	- -	≥ 5000 tcd cane crushing capacity	General Condition shall apply
5(k)	Induction/arc furnaces/cupola furnaces 5TPH or more	- -	All projects	General Condition shall apply
6		Service Sectors		
6(a)	Oil & gas transportation pipe line (crude and refinery/ petrochemical products), passing through national parks /sanctuaries/coral reefs /ecologically sensitive areas including LNG Terminal	All projects -		-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6(b)	Isolated storage & handling of hazardous chemicals (As per threshold planning quantity indicated in column 3 of schedule 2 & 3 of MSIHC Rules 1989 amended 2000)	-	All projects	General Condition shall apply
7		Physical Infrastructure including Environmental Services		
7(a)	Air ports	All projects	-	-
7(b)	All ship breaking yards including ship breaking units	All projects	-	-
7(c)	Industrial estates/parks/ complexes/ areas, export processing Zones (EPZs), Special Economic Zones (SEZs), Biotech Parks, Leather Complexes.	If at least one industry in the proposed industrial estate falls under the Category A, entire industrial area shall be treated as Category A, irrespective of the area. Industrial estates with area greater than 500 ha. and housing at least one Category B industry.	-Industrial estates housing at least one Category B industry and area <500 ha. Industrial estates of area > 500 ha. and not housing any industry belonging to Category A or B.	Special condition shall apply Note: Industrial Estate of area below 500 ha. and not housing any industry of category A or B does not require clearance.
7(d)	Common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs)	All integrated facilities having incineration & landfill or incineration alone	All facilities having land fill only	General Condition shall apply

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7(e)	Ports, Harbours	≥ 5 million TPA of cargo handling capacity (excluding fishing harbours)	< 5 million TPA of cargo handling capacity and/or ports/ harbours ≥10,000 TPA of fish handling capacity	General Condition shall apply
7(f)	Highways	i) New National High ways; and ii) Expansion of National High ways greater than 30 KM, involving additional right of way greater than 20m involving land acquisition and passing through more than one State.	i) New State High ways; and ii) Expansion of National / State Highways greater than 30 km involving additional right of way greater than 20m involving land acquisition.	General Condition shall apply
7(g)	Aerial ropeways		All projects	General Condition shall apply
7(h)	Common Effluent Treatment Plants (CETPs)		All projects	General Condition shall apply
7(i)	Common Municipal Solid Waste Management Facility (CMSWMF)		All projects	General Condition shall apply

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8		Building /Construction projects/Area Development projects and Townships		
8(a)	Building and Construction projects		≥20000 sq.mtrs and <1,50,000 sq.mtrs. of built-up area#	#(built up area for covered construction; in the case of facilities open to the sky, it will be the activity area)
8(b)	Townships and Area Development projects.		Covering an area ≥ 50 ha and or built up area ≥1,50,000 sq .mtrs ++	++All projects under Item 8(b) shall be appraised as Category B1

Note:-

General Condition (GC):

Any project or activity specified in Category 'B' will be treated as Category A, if located in whole or in part within 10 km from the boundary of: (i) Protected Areas notified under the Wild Life (Protection) Act, 1972, (ii) Critically Polluted areas as notified by the Central Pollution Control Board from time to time, (iii) Notified Eco-sensitive areas, (iv) inter-State boundaries and international boundaries.

Specific Condition (SC):

If any Industrial Estate/Complex / Export processing Zones /Special Economic Zones/Biotech Parks / Leather Complex with homogeneous type of industries such as Items 4(d), 4(f), 5(e), 5(f), or those Industrial estates with pre –defined set of activities (not necessarily homogeneous, obtains prior environmental clearance, individual industries including proposed industrial housing within such estates /complexes will not be required to take prior environmental clearance, so long as the Terms and Conditions for the industrial estate/complex are complied with (Such estates/complexes must have a clearly identified management with the legal responsibility of ensuring adherence to the Terms and Conditions of prior environmental clearance, who may be held responsible for violation of the same throughout the life of the complex/estate).

APPENDIX I

(See paragraph – 6)

FORM I

(I) **Basic Information**

Name of the Project:

Location / site alternatives under consideration:

Size of the Project: *

Expected cost of the project:

Contact Information:

Screening Category:

- *Capacity corresponding to sectoral activity (such as production capacity for manufacturing, mining lease area and production capacity for mineral production, area for mineral exploration, length for linear transport infrastructure, generation capacity for power generation etc.,)*

(II) **Activity**

1. **Construction, operation or decommissioning of the Project involving actions, which will cause physical changes in the locality (topography, land use, changes in water bodies, etc.)**

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities /rates, wherever possible) with source of information data
1.1	Permanent or temporary change in land use, land cover or topography including increase in intensity of land use (with respect to local land use plan)		
1.2	Clearance of existing land, vegetation and buildings?		
1.3	Creation of new land uses?		
1.4	Pre-construction investigations e.g. bore houses, soil testing?		
1.5	Construction works?		

1.6	Demolition works?		
1.7	Temporary sites used for construction works or housing of construction workers?		
1.8	Above ground buildings, structures or earthworks including linear structures, cut and fill or excavations		
1.9	Underground works including mining or tunneling?		
1.10	Reclamation works?		
1.11	Dredging?		
1.12	Offshore structures?		
1.13	Production and manufacturing processes?		
1.14	Facilities for storage of goods or materials?		
1.15	Facilities for treatment or disposal of solid waste or liquid effluents?		
1.16	Facilities for long term housing of operational workers?		
1.17	New road, rail or sea traffic during construction or operation?		
1.18	New road, rail, air waterborne or other transport infrastructure including new or altered routes and stations, ports, airports etc?		
1.19	Closure or diversion of existing transport routes or infrastructure leading to changes in traffic movements?		
1.20	New or diverted transmission lines or pipelines?		
1.21	Impoundment, damming, culverting, realignment or other changes to the hydrology of watercourses or aquifers?		
1.22	Stream crossings?		
1.23	Abstraction or transfers of water form ground or surface waters?		
1.24	Changes in water bodies or the land surface affecting drainage or run-off?		

1.25	Transport of personnel or materials for construction, operation or decommissioning?		
1.26	Long-term dismantling or decommissioning or restoration works?		
1.27	Ongoing activity during decommissioning which could have an impact on the environment?		
1.28	Influx of people to an area in either temporarily or permanently?		
1.29	Introduction of alien species?		
1.30	Loss of native species or genetic diversity?		
1.31	Any other actions?		

2. Use of Natural resources for construction or operation of the Project (such as land, water, materials or energy, especially any resources which are non-renewable or in short supply):

S.No.	Information/checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities /rates, wherever possible) with source of information data
2.1	Land especially undeveloped or agricultural land (ha)		
2.2	Water (expected source & competing users) unit: KLD		
2.3	Minerals (MT)		
2.4	Construction material – stone, aggregates, and / soil (expected source – MT)		
2.5	Forests and timber (source – MT)		
2.6	Energy including electricity and fuels (source, competing users) Unit: fuel (MT), energy (MW)		
2.7	Any other natural resources (use appropriate standard units)		

3. Use, storage, transport, handling or production of substances or materials, which could be harmful to human health or the environment or raise concerns about actual or perceived risks to human health.

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
3.1	Use of substances or materials, which are hazardous (as per MSIHC rules) to human health or the environment (flora, fauna, and water supplies)		
3.2	Changes in occurrence of disease or affect disease vectors (e.g. insect or water borne diseases)		
3.3	Affect the welfare of people e.g. by changing living conditions?		
3.4	Vulnerable groups of people who could be affected by the project e.g. hospital patients, children, the elderly etc.,		
3.5	Any other causes		

4. Production of solid wastes during construction or operation or decommissioning (MT/month)

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
4.1	Spoil, overburden or mine wastes		
4.2	Municipal waste (domestic and or commercial wastes)		
4.3	Hazardous wastes (as per Hazardous Waste Management Rules)		

4.4	Other industrial process wastes		
4.5	Surplus product		
4.6	Sewage sludge or other sludge from effluent treatment		
4.7	Construction or demolition wastes		
4.8	Redundant machinery or equipment		
4.9	Contaminated soils or other materials		
4.10	Agricultural wastes		
4.11	Other solid wastes		

5. Release of pollutants or any hazardous, toxic or noxious substances to air (Kg/hr)

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
5.1	Emissions from combustion of fossil fuels from stationary or mobile sources		
5.2	Emissions from production processes		
5.3	Emissions from materials handling including storage or transport		
5.4	Emissions from construction activities including plant and equipment		
5.5	Dust or odours from handling of materials including construction materials, sewage and waste		

5.6	Emissions from incineration of waste		
5.7	Emissions from burning of waste in open air (e.g. slash materials, construction debris)		
5.8	Emissions from any other sources		

6. Generation of Noise and Vibration, and Emissions of Light and Heat:

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data with source of information data
6.1	From operation of equipment e.g. engines, ventilation plant, crushers		
6.2	From industrial or similar processes		
6.3	From construction or demolition		
6.4	From blasting or piling		
6.5	From construction or operational traffic		
6.6	From lighting or cooling systems		
6.7	From any other sources		

7. Risks of contamination of land or water from releases of pollutants into the ground or into sewers, surface waters, groundwater, coastal waters or the sea:

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
7.1	From handling, storage, use or spillage of hazardous materials		
7.2	From discharge of sewage or other effluents to water or the land (expected mode and place of discharge)		
7.3	By deposition of pollutants emitted to air into the land or into water		
7.4	From any other sources		
7.5	Is there a risk of long term build up of pollutants in the environment from these sources?		

8. Risk of accidents during construction or operation of the Project, which could affect human health or the environment

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
8.1	From explosions, spillages, fires etc from storage, handling, use or production of hazardous substances		
8.2	From any other causes		
8.3	Could the project be affected by natural disasters causing environmental damage (e.g. floods, earthquakes, landslides, cloudburst etc)?		

9. Factors which should be considered (such as consequential development) which could lead to environmental effects or the potential for cumulative impacts with other existing or planned activities in the locality

S. No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
9.1	<p>Lead to development of supporting, ancillary development or development stimulated by the project which could have impact on the environment e.g.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supporting infrastructure (roads, power supply, waste or waste water treatment, etc.) • housing development • extractive industries • supply industries • other 		
9.2	Lead to after-use of the site, which could have an impact on the environment		
9.3	Set a precedent for later developments		
9.4	Have cumulative effects due to proximity to other existing or planned projects with similar effects		

(III) Environmental Sensitivity

S.No.	Areas	Name/ Identity	Aerial distance (within 15 km.) Proposed project location boundary
1	Areas protected under international conventions, national or local legislation for their ecological, landscape, cultural or other related value		

2	Areas which are important or sensitive for ecological reasons - Wetlands, watercourses or other water bodies, coastal zone, biospheres, mountains, forests		
3	Areas used by protected, important or sensitive species of flora or fauna for breeding, nesting, foraging, resting, over wintering, migration		
4	Inland, coastal, marine or underground waters		
5	State, National boundaries		
6	Routes or facilities used by the public for access to recreation or other tourist, pilgrim areas		
7	Defence installations		
8	Densely populated or built-up area		
9	Areas occupied by sensitive man-made land uses (<i>hospitals, schools, places of worship, community facilities</i>)		
10	Areas containing important, high quality or scarce resources (<i>ground water resources, surface resources, forestry, agriculture, fisheries, tourism, minerals</i>)		
11	Areas already subjected to pollution or environmental damage. (<i>those where existing legal environmental standards are exceeded</i>)		
12	Areas susceptible to natural hazard which could cause the project to present environmental problems (<i>earthquakes, subsidence, landslides, erosion, flooding or extreme or adverse climatic conditions</i>)		

(IV). Proposed Terms of Reference for EIA studies

APPENDIX II

(See paragraph 6)

FORM-1 A (only for construction projects listed under item 8 of the Schedule)

CHECK LIST OF ENVIRONMENTAL IMPACTS

(Project proponents are required to provide full information and wherever necessary attach explanatory notes with the Form and submit along with proposed environmental management plan & monitoring programme)

1. LAND ENVIRONMENT

(Attach panoramic view of the project site and the vicinity)

1.1. Will the existing landuse get significantly altered from the project that is not consistent with the surroundings? (Proposed landuse must conform to the approved Master Plan / Development Plan of the area. Change of landuse if any and the statutory approval from the competent authority be submitted). Attach Maps of (i) site location, (ii) surrounding features of the proposed site (within 500 meters) and (iii) the site (indicating levels & contours) to appropriate scales. If not available attach only conceptual plans.

1.2. List out all the major project requirements in terms of the land area, built up area, water consumption, power requirement, connectivity, community facilities, parking needs etc.

1.3. What are the likely impacts of the proposed activity on the existing facilities adjacent to the proposed site? (Such as open spaces, community facilities, details of the existing landuse, disturbance to the local ecology).

1.4. Will there be any significant land disturbance resulting in erosion, subsidence & instability? (Details of soil type, slope analysis, vulnerability to subsidence, seismicity etc may be given).

1.5. Will the proposal involve alteration of natural drainage systems? (Give details on a contour map showing the natural drainage near the proposed project site)

1.6. What are the quantities of earthwork involved in the construction activity-cutting, filling, reclamation etc. (Give details of the quantities of earthwork involved, transport of fill materials from outside the site etc.)

1.7. Give details regarding water supply, waste handling etc during the construction period.

1.8. Will the low lying areas & wetlands get altered? (Provide details of how low lying and wetlands are getting modified from the proposed activity)

1.9. Whether construction debris & waste during construction cause health hazard? (Give quantities of various types of wastes generated during construction including the construction labour and the means of disposal)

2. WATER ENVIRONMENT

2.1. Give the total quantity of water requirement for the proposed project with the breakup of requirements for various uses. How will the water requirement met? State the sources & quantities and furnish a water balance statement.

- 2.2. What is the capacity (dependable flow or yield) of the proposed source of water?
- 2.3. What is the quality of water required, in case, the supply is not from a municipal source? (Provide physical, chemical, biological characteristics with class of water quality)
- 2.4. How much of the water requirement can be met from the recycling of treated wastewater? (Give the details of quantities, sources and usage)
- 2.5. Will there be diversion of water from other users? (Please assess the impacts of the project on other existing uses and quantities of consumption)
- 2.6. What is the incremental pollution load from wastewater generated from the proposed activity? (Give details of the quantities and composition of wastewater generated from the proposed activity)
- 2.7. Give details of the water requirements met from water harvesting? Furnish details of the facilities created.
- 2.8. What would be the impact of the land use changes occurring due to the proposed project on the runoff characteristics (quantitative as well as qualitative) of the area in the post construction phase on a long term basis? Would it aggravate the problems of flooding or water logging in any way?
- 2.9. What are the impacts of the proposal on the ground water? (Will there be tapping of ground water; give the details of ground water table, recharging capacity, and approvals obtained from competent authority, if any)
- 2.10. What precautions/measures are taken to prevent the run-off from construction activities polluting land & aquifers? (Give details of quantities and the measures taken to avoid the adverse impacts)
- 2.11. How is the storm water from within the site managed?(State the provisions made to avoid flooding of the area, details of the drainage facilities provided along with a site layout indication contour levels)
- 2.12. Will the deployment of construction labourers particularly in the peak period lead to unsanitary conditions around the project site (Justify with proper explanation)
- 2.13. What on-site facilities are provided for the collection, treatment & safe disposal of sewage? (Give details of the quantities of wastewater generation, treatment capacities with technology & facilities for recycling and disposal)
- 2.14. Give details of dual plumbing system if treated waste used is used for flushing of toilets or any other use.

3. VEGETATION

- 3.1. Is there any threat of the project to the biodiversity? (Give a description of the local ecosystem with it's unique features, if any)

3.2. Will the construction involve extensive clearing or modification of vegetation? (Provide a detailed account of the trees & vegetation affected by the project)

3.3. What are the measures proposed to be taken to minimize the likely impacts on important site features (Give details of proposal for tree plantation, landscaping, creation of water bodies etc along with a layout plan to an appropriate scale)

4. FAUNA

4.1. Is there likely to be any displacement of fauna- both terrestrial and aquatic or creation of barriers for their movement? Provide the details.

4.2. Any direct or indirect impacts on the avifauna of the area? Provide details.

4.3. Prescribe measures such as corridors, fish ladders etc to mitigate adverse impacts on fauna

5. AIR ENVIRONMENT

5.1. Will the project increase atmospheric concentration of gases & result in heat islands? (Give details of background air quality levels with predicted values based on dispersion models taking into account the increased traffic generation as a result of the proposed constructions)

5.2. What are the impacts on generation of dust, smoke, odorous fumes or other hazardous gases? Give details in relation to all the meteorological parameters.

5.3. Will the proposal create shortage of parking space for vehicles? Furnish details of the present level of transport infrastructure and measures proposed for improvement including the traffic management at the entry & exit to the project site.

5.4. Provide details of the movement patterns with internal roads, bicycle tracks, pedestrian pathways, footpaths etc., with areas under each category.

5.5. Will there be significant increase in traffic noise & vibrations? Give details of the sources and the measures proposed for mitigation of the above.

5.6. What will be the impact of DG sets & other equipment on noise levels & vibration in & ambient air quality around the project site? Provide details.

6. AESTHETICS

6.1. Will the proposed constructions in any way result in the obstruction of a view, scenic amenity or landscapes? Are these considerations taken into account by the proponents?

6.2. Will there be any adverse impacts from new constructions on the existing structures? What are the considerations taken into account?

6.3. Whether there are any local considerations of urban form & urban design influencing the design criteria? They may be explicitly spelt out.

6.4. Are there any anthropological or archaeological sites or artefacts nearby? State if any other significant features in the vicinity of the proposed-site have been considered.

7. SOCIO-ECONOMIC ASPECTS

7.1. Will the proposal result in any changes to the demographic structure of local population? Provide the details.

7.2. Give details of the existing social infrastructure around the proposed project.

7.3. Will the project cause adverse effects on local communities, disturbance to sacred sites or other cultural values? What are the safeguards proposed?

8. BUILDING MATERIALS

8.1. May involve the use of building materials with high-embodied energy. Are the construction materials produced with energy efficient processes? (Give details of energy conservation measures in the selection of building materials and their energy efficiency)

8.2. Transport and handling of materials during construction may result in pollution, noise & public nuisance. What measures are taken to minimize the impacts?

8.3. Are recycled materials used in roads and structures? State the extent of savings achieved?

8.4. Give details of the methods of collection, segregation & disposal of the garbage generated during the operation phases of the project.

9. ENERGY CONSERVATION

9.1. Give details of the power requirements, source of supply, backup source etc. What is the energy consumption assumed per square foot of built-up area? How have you tried to minimize energy consumption?

9.2. What type of, and capacity of, power back-up to you plan to provide?

9.3. What are the characteristics of the glass you plan to use? Provide specifications of its characteristics related to both short wave and long wave radiation?

9.4. What passive solar architectural features are being used in the building? Illustrate the applications made in the proposed project.

9.5. Does the layout of streets & buildings maximise the potential for solar energy devices? Have you considered the use of street lighting, emergency lighting and solar hot water systems for use in the building complex? Substantiate with details.

9.6. Is shading effectively used to reduce cooling/heating loads? What principles have been used to maximize the shading of Walls on the East and the West and the Roof? How much energy saving has been effected?

9.7. Do the structures use energy-efficient space conditioning, lighting and mechanical systems? Provide technical details. Provide details of the transformers and motor efficiencies, lighting intensity and air-conditioning load assumptions? Are you using CFC and HCFC free chillers? Provide specifications.

9.8. What are the likely effects of the building activity in altering the micro-climates? Provide a self assessment on the likely impacts of the proposed construction on creation of heat island & inversion effects?

9.9. What are the thermal characteristics of the building envelope? (a) roof; (b) external walls; and (c) fenestration? Give details of the material used and the U-values or the R values of the individual components.

9.10. What precautions & safety measures are proposed against fire hazards? Furnish details of emergency plans.

9.11. If you are using glass as wall material provides details and specifications including emissivity and thermal characteristics.

9.12. What is the rate of air infiltration into the building? Provide details of how you are mitigating the effects of infiltration.

9.13. To what extent the non-conventional energy technologies are utilised in the overall energy consumption? Provide details of the renewable energy technologies used.

10. Environment Management Plan

The Environment Management Plan would consist of all mitigation measures for each item wise activity to be undertaken during the construction, operation and the entire life cycle to minimize adverse environmental impacts as a result of the activities of the project. It would also delineate the environmental monitoring plan for compliance of various environmental regulations. It will state the steps to be taken in case of emergency such as accidents at the site including fire.

APPENDIX III

(See paragraph 7

GENERIC STRUCTURE OF ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESMENT DOCUMENT

S.NO	EIA STRUCTURE	CONTENTS
1.	Introduction	<ul style="list-style-type: none">• Purpose of the report• Identification of project & project proponent• Brief description of nature, size, location of the project and its importance to the country, region• Scope of the study – details of regulatory scoping carried out (As per Terms of Reference)
2.	Project Description	<ul style="list-style-type: none">• Condensed description of those aspects of the project (based on project feasibility study), likely to cause environmental effects. Details should be provided to give clear picture of the following:<ul style="list-style-type: none">• Type of project• Need for the project• Location (maps showing general location, specific location, project boundary & project site layout)• Size or magnitude of operation (incl. Associated activities required by or for the project)• Proposed schedule for approval and implementation• Technology and process description• Project description. Including drawings showing project layout, components of project etc. Schematic representations of the feasibility drawings which give information important for EIA purpose• Description of mitigation measures incorporated into the project to meet environmental standards, environmental operating conditions, or other EIA requirements (as required by the scope)• Assessment of New & untested technology for the risk of technological failure

3.	Description of the Environment	<ul style="list-style-type: none"> • Study area, period, components & methodology • Establishment of baseline for valued environmental components, as identified in the scope • Base maps of all environmental components
4.	Anticipated Environmental Impacts & Mitigation Measures	<ul style="list-style-type: none"> • Details of Investigated Environmental impacts due to project location, possible accidents, project design, project construction, regular operations, final decommissioning or rehabilitation of a completed project • Measures for minimizing and / or offsetting adverse impacts identified • Irreversible and Irretrievable commitments of environmental components • Assessment of significance of impacts (Criteria for determining significance, Assigning significance) • Mitigation measures
5.	Analysis of Alternatives (Technology & Site)	<ul style="list-style-type: none"> • In case, the scoping exercise results in need for alternatives: • Description of each alternative • Summary of adverse impacts of each alternative • Mitigation measures proposed for each alternative and • Selection of alternative
6.	Environmental Monitoring Program	<ul style="list-style-type: none"> • Technical aspects of monitoring the effectiveness of mitigation measures (incl. Measurement methodologies, frequency, location, data analysis, reporting schedules, emergency procedures, detailed budget & procurement schedules)
7.	Additional Studies	<ul style="list-style-type: none"> • Public Consultation • Risk assessment • Social Impact Assessment. R&R Action Plans
8.	Project Benefits	<ul style="list-style-type: none"> • Improvements in the physical infrastructure • Improvements in the social infrastructure • Employment potential –skilled; semi-skilled and unskilled • Other tangible benefits

9.	Environmental Cost Benefit Analysis	If recommended at the Scoping stage
10.	EMP	<ul style="list-style-type: none"> • Description of the administrative aspects of ensuring that mitigative measures are implemented and their effectiveness monitored, after approval of the EIA
11	Summary & Conclusion (This will constitute the summary of the EIA Report)	<ul style="list-style-type: none"> • Overall justification for implementation of the project • Explanation of how, adverse effects have been mitigated
12.	Disclosure of Consultants engaged	<ul style="list-style-type: none"> • The names of the Consultants engaged with their brief resume and nature of Consultancy rendered

APPENDIX III A
(See paragraph 7)

CONTENTS OF SUMMARY ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT

The Summary EIA shall be a summary of the full EIA Report condensed to ten A-4 size pages at the maximum. It should necessarily cover in brief the following Chapters of the full EIA Report: -

1. Project Description
2. Description of the Environment
3. Anticipated Environmental impacts and mitigation measures
4. Environmental Monitoring Programme
5. Additional Studies
6. Project Benefits
7. Environment Management Plan

APPENDIX IV
(See paragraph 7)

PROCEDURE FOR CONDUCT OF PUBLIC HEARING

1.0 The Public Hearing shall be arranged in a systematic, time bound and transparent manner ensuring widest possible public participation at the project site(s) or in its close proximity District -wise, by the concerned State Pollution Control Board (SPCB) or the Union Territory Pollution Control Committee (UTPCC).

2.0 The Process:

2.1 The Applicant shall make a request through a simple letter to the Member Secretary of the SPCB or Union Territory Pollution Control Committee, in whose jurisdiction the project is located, to arrange the public hearing within the prescribed statutory period. In case the project site is extending beyond a State or Union Territory, the public hearing is mandated in each State or Union Territory in which the project is sited and the Applicant shall make separate requests to each concerned SPCB or UTPCC for holding the public hearing as per this procedure.

2.2 The Applicant shall enclose with the letter of request, at least 10 hard copies and an equivalent number of soft (electronic) copies of the draft EIA Report with the generic structure given in Appendix III including the Summary Environment Impact Assessment report in English and in the local language, prepared strictly in accordance with the Terms of Reference communicated after Scoping (Stage-2). Simultaneously the applicant shall arrange to forward copies, one hard and one soft, of the above draft EIA Report along with the Summary EIA report to the Ministry of Environment and Forests and to the following authorities or offices, within whose jurisdiction the project will be located:

- (a) District Magistrate/s
- (b) Zila Parishad or Municipal Corporation
- (c) District Industries Office
- (d) Concerned Regional Office of the Ministry of Environment and Forests

2.3 On receiving the draft Environmental Impact Assessment report, the above-mentioned authorities except the MoEF, shall arrange to widely publicize it within their respective jurisdictions requesting the interested persons to send their comments to the concerned regulatory authorities. They shall also make available the draft EIA Report for inspection electronically or otherwise to the public during normal office hours till the Public Hearing is over. The Ministry of Environment and Forests shall promptly display the Summary of the draft Environmental Impact Assessment report on its website, and also make the full draft EIA available for reference at a notified place during normal office hours in the Ministry at Delhi.

2.4 The SPCB or UTPCC concerned shall also make similar arrangements for giving publicity about the project within the State/Union Territory and make available the Summary of the draft Environmental Impact Assessment report (Appendix III A) for inspection in select offices or public libraries or panchayats etc. They shall also additionally

make available a copy of the draft Environmental Impact Assessment report to the above five authorities/offices viz. Ministry of Environment and Forests, District Magistrate etc.

3.0 Notice of Public Hearing:

3.1 The Member-Secretary of the concerned SPCB or UTPCC shall finalize the date, time and exact venue for the conduct of public hearing within 7(seven) days of the date of receipt of the draft Environmental Impact Assessment report from the project proponent, and advertise the same in one major National Daily and one Regional vernacular Daily. A minimum notice period of 30(thirty) days shall be provided to the public for furnishing their responses;

3.2 The advertisement shall also inform the public about the places or offices where the public could access the draft Environmental Impact Assessment report and the Summary Environmental Impact Assessment report before the public hearing.

3.3 No postponement of the date, time, venue of the public hearing shall be undertaken, unless some untoward emergency situation occurs and only on the recommendation of the concerned District Magistrate the postponement shall be notified to the public through the same National and Regional vernacular dailies and also prominently displayed at all the identified offices by the concerned SPCB or Union Territory Pollution Control Committee;

3.4 In the above exceptional circumstances fresh date, time and venue for the public consultation shall be decided by the Member –Secretary of the concerned SPCB or UTPCC only in consultation with the District Magistrate and notified afresh as per procedure under 3.1 above.

4.0 The Panel

4.1 The District Magistrate or his or her representative not below the rank of an Additional District Magistrate assisted by a representative of SPCB or UTPCC, shall supervise and preside over the entire public hearing process.

5.0 Videography

5.1 The SPCB or UTPCC shall arrange to video film the entire proceedings. A copy of the videotape or a CD shall be enclosed with the public hearing proceedings while forwarding it to the Regulatory Authority concerned.

6.0 Proceedings

6.1 The attendance of all those who are present at the venue shall be noted and annexed with the final proceedings.

6.2 There shall be no quorum required for attendance for starting the proceedings.

6.3 A representative of the applicant shall initiate the proceedings with a presentation on the project and the Summary EIA report.

6.4 Every person present at the venue shall be granted the opportunity to seek information or clarifications on the project from the Applicant. The summary of the public

hearing proceedings accurately reflecting all the views and concerns expressed shall be recorded by the representative of the SPCB or UTPCC and read over to the audience at the end of the proceedings explaining the contents in the vernacular language and the agreed minutes shall be signed by the District Magistrate or his or her representative on the same day and forwarded to the SPCB/UTPCC concerned.

6.5 A Statement of the issues raised by the public and the comments of the Applicant shall also be prepared in the local language and in English and annexed to the proceedings:

6.6 The proceedings of the public hearing shall be conspicuously displayed at the office of the Panchyats within whose jurisdiction the project is located, office of the concerned Zila Parishad, District Magistrate, and the SPCB or UTPCC. The SPCB or UTPCC shall also display the proceedings on its website for general information. Comments, if any, on the proceedings which may be sent directly to the concerned regulatory authorities and the Applicant concerned.

7.0 Time period for completion of public hearing

7.1 The public hearing shall be completed within a period of 45 (forty five) days from date of receipt of the request letter from the Applicant. Therefore the SPCB or UTPCC concerned shall send the public hearing proceedings to the concerned regulatory authority within 8(eight) days of the completion of the public hearing. The applicant may also directly forward a copy of the approved public hearing proceedings to the regulatory authority concerned along with the final Environmental Impact Assessment report or supplementary report to the draft EIA report prepared after the public hearing and public consultations.

7.2 If the SPCB or UTPCC fails to hold the public hearing within the stipulated 45(forty five) days, the Central Government in Ministry of Environment and Forests for Category 'A' project or activity and the State Government or Union Territory Administration for Category 'B' project or activity at the request of the SEIAA, shall engage any other agency or authority to complete the process, as per procedure laid down in this notification.

APPENDIX -V
(See paragraph 7)

PROCEDURE PRESCRIBED FOR APPRAISAL

1. The applicant shall apply to the concerned regulatory authority through a simple communication enclosing the following documents where public consultations are mandatory: -

- Final Environment Impact Assessment Report [20(twenty) hard copies and 1 (one) soft copy]
- A copy of the video tape or CD of the public hearing proceedings
- A copy of final layout plan (20 copies)
- A copy of the project feasibility report (1 copy)

2. The Final EIA Report and the other relevant documents submitted by the applicant shall be scrutinized in office within 30 days from the date of its receipt by the concerned Regulatory Authority strictly with reference to the TOR and the inadequacies noted shall be communicated electronically or otherwise in a single set to the Members of the EAC /SEAC enclosing a copy each of the Final EIA Report including the public hearing proceedings and other public responses received along with a copy of Form -1or Form 1A and scheduled date of the EAC /SEAC meeting for considering the proposal .

3. Where a public consultation is not mandatory and therefore a formal EIA study is not required, the appraisal shall be made on the basis of the prescribed application Form 1 and a pre-feasibility report in the case of all projects and activities other than Item 8 of the Schedule .In the case of Item 8 of the Schedule, considering its unique project cycle , the EAC or SEAC concerned shall appraise all Category B projects or activities on the basis of Form 1, Form 1A and the conceptual plan and stipulate the conditions for environmental clearance . As and when the applicant submits the approved scheme /building plans complying with the stipulated environmental clearance conditions with all other necessary statutory approvals, the EAC /SEAC shall recommend the grant of environmental clearance to the competent authority.

4. Every application shall be placed before the EAC /SEAC and its appraisal completed within 60 days of its receipt with requisite documents / details in the prescribed manner.

5. The applicant shall be informed at least 15 (fifteen) days prior to the scheduled date of the EAC /SEAC meeting for considering the project proposal.

6. The minutes of the EAC /SEAC meeting shall be finalised within 5 working days of the meeting and displayed on the website of the concerned regulatory authority. In case the project or activity is recommended for grant of EC, then the minutes shall clearly list out the specific environmental safeguards and conditions. In case the recommendations are for rejection, the reasons for the same shall also be explicitly stated.

APPENDIX VI
(See paragraph 5)

COMPOSITION OF THE SECTOR/ PROJECT SPECIFIC EXPERT APPRAISAL COMMITTEE (EAC) FOR CATEGORY A PROJECTS AND THE STATE/UT LEVEL EXPERT APPRAISAL COMMITTEES (SEACs) FOR CATEGORY B PROJECTS TO BE CONSTITUTED BY THE CENTRAL GOVERNMENT

1. The Expert Appraisal Committees (EAC(s) and the State/UT Level Expert Appraisal Committees (SEACs) shall consist of only professionals and experts fulfilling the following eligibility criteria:

Professional: The person should have at least (i) 5 years of formal University training in the concerned discipline leading to a MA/MSc Degree, or (ii) in case of Engineering /Technology/Architecture disciplines, 4 years formal training in a professional training course together with prescribed practical training in the field leading to a B.Tech/B.E./B.Arch. Degree, or (iii) Other professional degree (e.g. Law) involving a total of 5 years of formal University training and prescribed practical training, or (iv) Prescribed apprenticeship/article ship and pass examinations conducted by the concerned professional association (e.g. Chartered Accountancy),or (v) a University degree , followed by 2 years of formal training in a University or Service Academy (e.g. MBA/IAS/IFS). In selecting the individual professionals, experience gained by them in their respective fields will be taken note of.

Expert: A professional fulfilling the above eligibility criteria with at least 15 years of relevant experience in the field, or with an advanced degree (e.g. Ph.D.) in a concerned field and at least 10 years of relevant experience.

Age: Below 70 years. However, in the event of the non-availability of /paucity of experts in a given field, the maximum age of a member of the Expert Appraisal Committee may be allowed up to 75 years

2. The Members of the EAC shall be Experts with the requisite expertise and experience in the following fields /disciplines. In the event that persons fulfilling the criteria of "Experts" are not available, Professionals in the same field with sufficient experience may be considered:

- **Environment Quality Experts:** Experts in measurement/monitoring, analysis and interpretation of data in relation to environmental quality
- **Sectoral Experts in Project Management:** Experts in Project Management or Management of Process/Operations/Facilities in the relevant sectors.
- **Environmental Impact Assessment Process Experts:** Experts in conducting and carrying out Environmental Impact Assessments (EIAs) and preparation of Environmental Management Plans (EMPs) and other Management plans and who have wide expertise and knowledge of predictive techniques and tools used in the EIA process
- **Risk Assessment Experts**
- **Life Science Experts in floral and faunal management**
- **Forestry and Wildlife Experts**

• **Environmental Economics Expert with experience in project appraisal**

3. The Membership of the EAC shall not exceed 15 (fifteen) regular Members. However the Chairperson may co-opt an expert as a Member in a relevant field for a particular meeting of the Committee.
4. The Chairperson shall be an outstanding and experienced environmental policy expert or expert in management or public administration with wide experience in the relevant development sector.
5. The Chairperson shall nominate one of the Members as the Vice Chairperson who shall preside over the EAC in the absence of the Chairman /Chairperson.
6. A representative of the Ministry of Environment and Forests shall assist the Committee as its Secretary.
7. The maximum tenure of a Member, including Chairperson, shall be for 2 (two) terms of 3 (three) years each.
8. The Chairman / Members may not be removed prior to expiry of the tenure without cause and proper enquiry.

कार्यालय कार्यपालन अभियंता

लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

Email - ee.surajpur@nic.in

ee.pwdsuraj@gmail.com

Fax No. 07775-266276


बिन्दु क्रमांक - 10

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग, संभाग सूरजपुर द्वारा प्रस्तावित नवीन जिला कोर्ट भवन निर्माण में प्रभावित 1.82 हे. राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव अंतर्गत नवीन जिला कोर्ट भवन का प्रस्तावित लेआउट में बिना केन्द्रीय सरकार की अनुमति के पूर्व किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा, लेआउट की प्रति संलग्न है।

दिनांक : 8/03/2026

स्थान : सूरजपुर



कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. संभाग सूरजपुर

कार्यालय कार्यपालन अभियंता

लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

Email - ee.surajpur@nic.in

ee.pwdsuraj@gmail.com

Fax No. 07775-266276


बिन्दु क्रमांक - 11

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग, संभाग सूरजपुर द्वारा प्रस्तावित नवीन जिला कोर्ट भवन निर्माण में प्रभावित 1.82 हे. व्यपवर्तीत राजस्व वन भूमि पर निर्माण के दौरान किसी भी प्रकार के मजदुरो हेतु निवास का निर्माण नहीं किया जावेगा।

दिनांक : 8/03/2026

स्थान : सूरजपुर


कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. संभाग सूरजपुर

कार्यालय कार्यपालन अभियंता

लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

Email - ee.surajpur@nic.in

ee.pwdsuraj@gmail.com


Fax No. 07775-266276

बिन्दु क्रमांक - 12

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग, संभाग सूरजपुर द्वारा प्रस्तावित नवीन जिला कोर्ट भवन निर्माण में प्रभावित 1.82 हे. राजस्व वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव अंतर्गत भवन निर्माण में सम्मिलित मजदुरो को ईधन की व्यवस्था के पर्याप्त साधन वन विभाग या वन विकास निगम से खरीदकर, आवेदक संस्थान द्वारा कराया जावेगा।

दिनांक : 8/03/2026
स्थान : सूरजपुर


कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. संभाग सूरजपुर

कार्यालय कार्यपालन अभियंता

लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

Email - ee.surajpur@nic.in

ee.pwdsuraj@gmail.com


Fax No. 07775-266276

बिन्दु क्रमांक - 13

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग, संभाग सूरजपुर द्वारा प्रस्तावित नवीन जिला कोर्ट भवन निर्माण में प्रभावित 1.82 हे. राजस्व वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव अंतर्गत, प्रस्तावित राजस्व वन क्षेत्र का सिमेंट कांक्रीट पिल्हरों द्वारा सिमाकन वन मण्डलाधिकारी, सूरजपुर के निर्देशानुसार किया गया है।

दिनांक : ४/०३/२०२२
स्थान : सूरजपुर


कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. संभाग सूरजपुर

कार्यालय कार्यपालन अभियंता

लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

Email - ee.surajpur@nic.in

ee.pwdsuraj@gmail.com

Fax No. 07775-266276

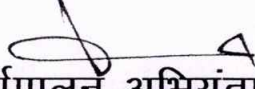
बिन्दु क्रमांक - 14

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग, संभाग सूरजपुर द्वारा प्रस्तावित नवीन जिला कोर्ट भवन निर्माण में प्रभावित 1.82 हे. राजस्व वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव अंतर्गत, भवन निर्माण हेतु प्रयुक्त सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र अंतर्गत अतिरिक्त मार्ग का निर्माण नहीं किया जावेगा।

दिनांक : 8/03/2022

स्थान : सूरजपुर


कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. संभाग सूरजपुर

कार्यालय कार्यपालन अभियंता

लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

Email - ee.surajpur@nic.in

ee.pwdsuraj@gmail.com

Fax No. 07775-266276


बिन्दु क्रमांक - 15

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग, संभाग सूरजपुर द्वारा प्रस्तावित नवीन जिला कोर्ट भवन निर्माण में प्रभावित 1.82 हे. राजस्व वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव अंतर्गत, वन भूमि का नियमानुसार निर्धारित पट्टे की अवधि संबंधी सभी निर्देशों का पालन संस्थान द्वारा किया जावेगा।

दिनांक : 8/03/2026

स्थान : सूरजपुर


कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. संभाग सूरजपुर

कार्यालय कार्यपालन अभियंता

लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सूरजपुर जिला--सूरजपुर (छ.ग.)

Email - ee.surajpur@nic.in

ee.pwdsuraj@gmail.com

Fax No. 07775-266276


बिन्दु क्रमांक - 16

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग, संभाग सूरजपुर द्वारा प्रस्तावित नवीन जिला कोर्ट भवन निर्माण में प्रभावित 1.82 हे. राजस्व वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव अंतर्गत, व्यपवर्तीत 1.82 हे. राजस्व वन भूमि का उपयोग केवल नवीन जिला कोर्ट भवन निर्माण हेतु किया जावेगा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जावेगा।

दिनांक : 8/03/2026

स्थान : सूरजपुर


कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. संभाग सूरजपुर

कार्यालय कार्यपालन अभियंता

लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

Email - ee.surajpur@nic.in

ee.pwdsuraj@gmail.com

Fax No. 07775-266276


बिन्दु क्रमांक - 17

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग, संभाग सूरजपुर द्वारा प्रस्तावित नवीन जिला कोर्ट भवन निर्माण में प्रभावित 1.82 हे. राजस्व वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव अंतर्गत, व्यपवर्तीत 1.82 हे. राजस्व वन भूमि को भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी अन्य संस्थान या विभाग को हस्तातरित नहीं किया जावेगा।

दिनांक : 8/03/2022

स्थान : सूरजपुर


कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. संभाग सूरजपुर

कार्यालय कार्यपालन अभियंता

लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

Email – ee.surajpur@nic.in

ee.pwdsuraj@gmail.com

Fax No. 07775-266276


बिन्दु क्रमांक – 18

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग, संभाग सूरजपुर द्वारा प्रस्तावित नवीन जिला कोर्ट भवन निर्माण में प्रभावित 1.82 हे. राजस्व वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव अंतर्गत, अधिरोपित किसी भी शर्तों, नियमों एवं निर्देशों का उलघन संस्थान द्वारा नहीं किया जावेगा।

दिनांक : ४/०३/२०२६

स्थान : सूरजपुर


कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. संभाग सूरजपुर

कार्यालय कार्यपालन अभियंता

लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

Email - ee.surajpur@nic.in

ee.pwdsuraj@gmail.com

Fax No. 07775-266276

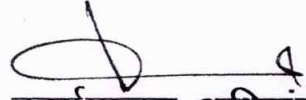
बिन्दु क्रमांक - 19

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग, संभाग सूरजपुर द्वारा प्रस्तावित नवीन जिला कोर्ट भवन निर्माण में प्रभावित 1.82 हे. राजस्व वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव अंतर्गत, वनों और वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा और विकास हेतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली कोई भी अन्य शर्त लागू होगी वह आवेदक संस्थान को मान्य होगी।

दिनांक : 8/03/2026

स्थान : सूरजपुर


कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. संभाग सूरजपुर

कार्यालय कार्यपालन अभियंता

लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

Email - ee.surajpur@nic.in

ee.pwdsuraj@gmail.com

Fax No. 07775-266276


बिन्दु क्रमांक - 20

प्रमाण पत्र

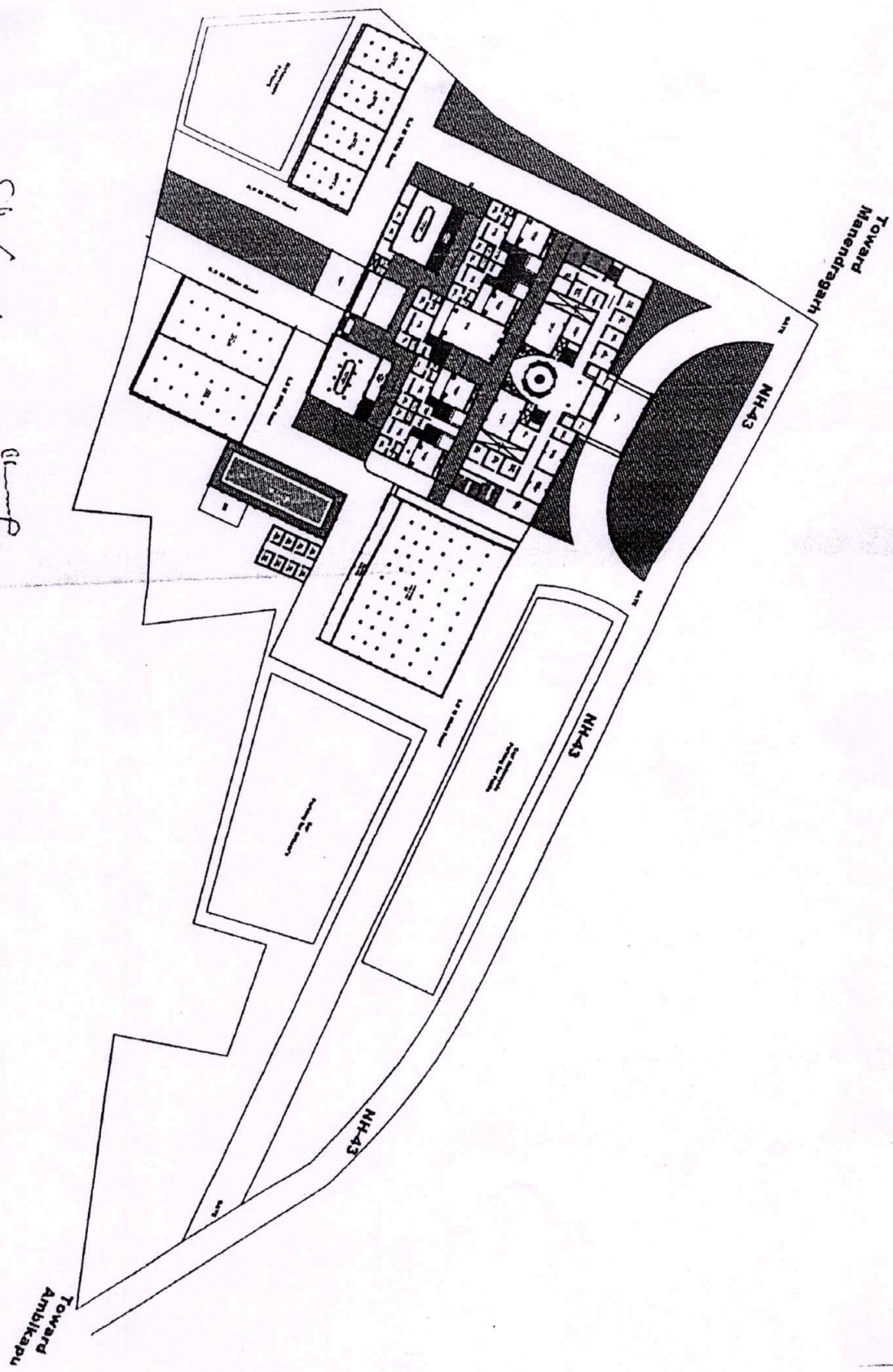
प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग, संभाग सूरजपुर द्वारा प्रस्तावित नवीन जिला कोर्ट भवन निर्माण में प्रभावित 1.82 हे. राजस्व वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव अंतर्गत, अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in/>) में अपलोड किया जावेगा।

दिनांक : 8/03/2026

स्थान : सूरजपुर


कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. संभाग सूरजपुर

SITE PLAN OF DISTRICT COURT SURAJPUR

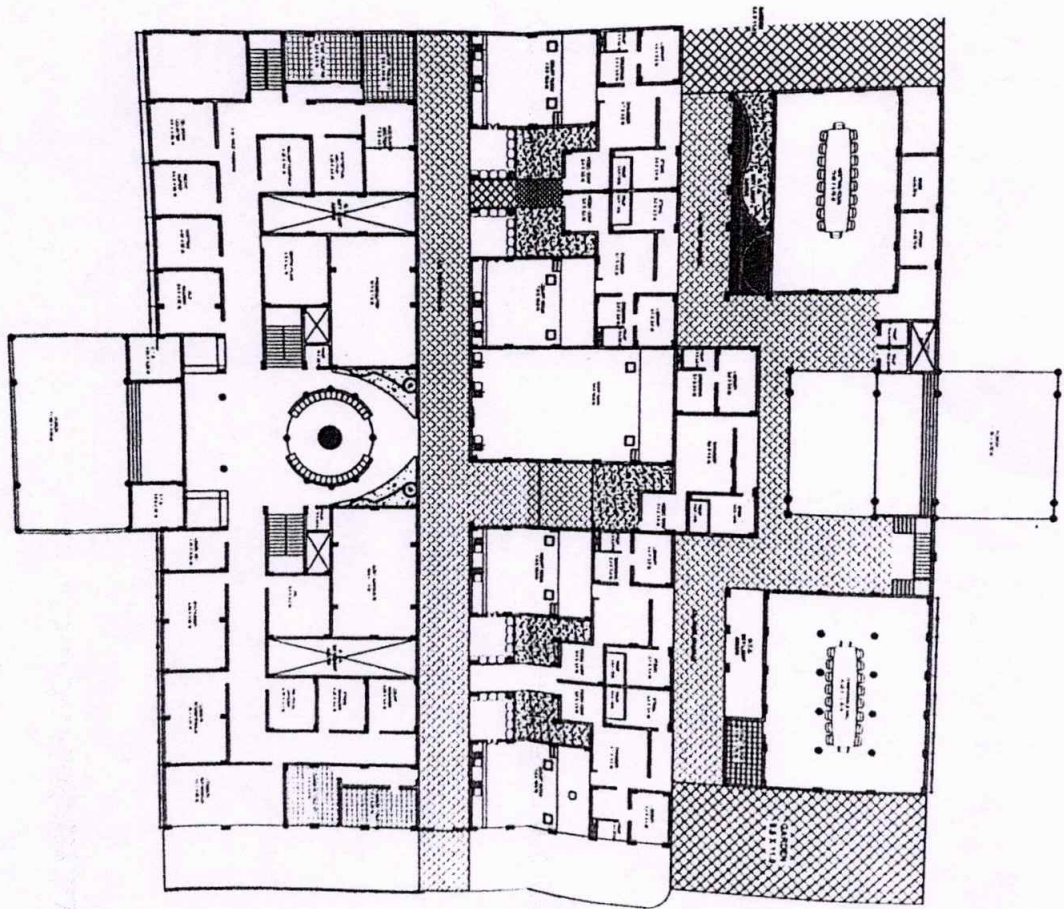


ENGINEER
PMD SURAJPUR

SUB DIVISIONAL OFFICER
PMD SUB DIVISION SURAJPUR

EXECUTIVE ENGINEER
PMD SURAJPUR

**GROUND FLOOR PLAN OF DISTRICT COURT
BUILDING SURAJPUR(CG)**



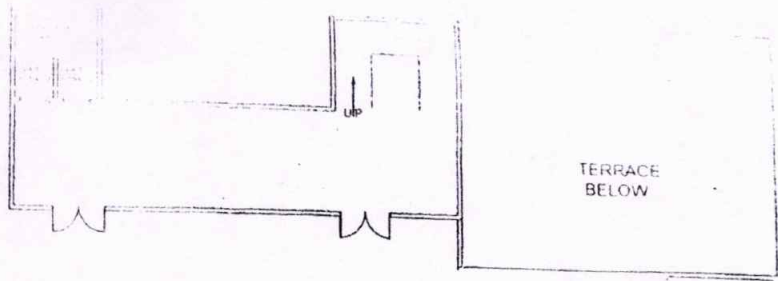
**SUB ENGINEER
PMD SURAJPUR**

**SUB DIVISIONSL OFFICER
PMD SUB DIVISION SURAJPUR**

**EXECUTIVE ENGINEER
PMD SUB DIVISION SURAJPUR**

NOTICE
BELOW

OPEN
TERRACE

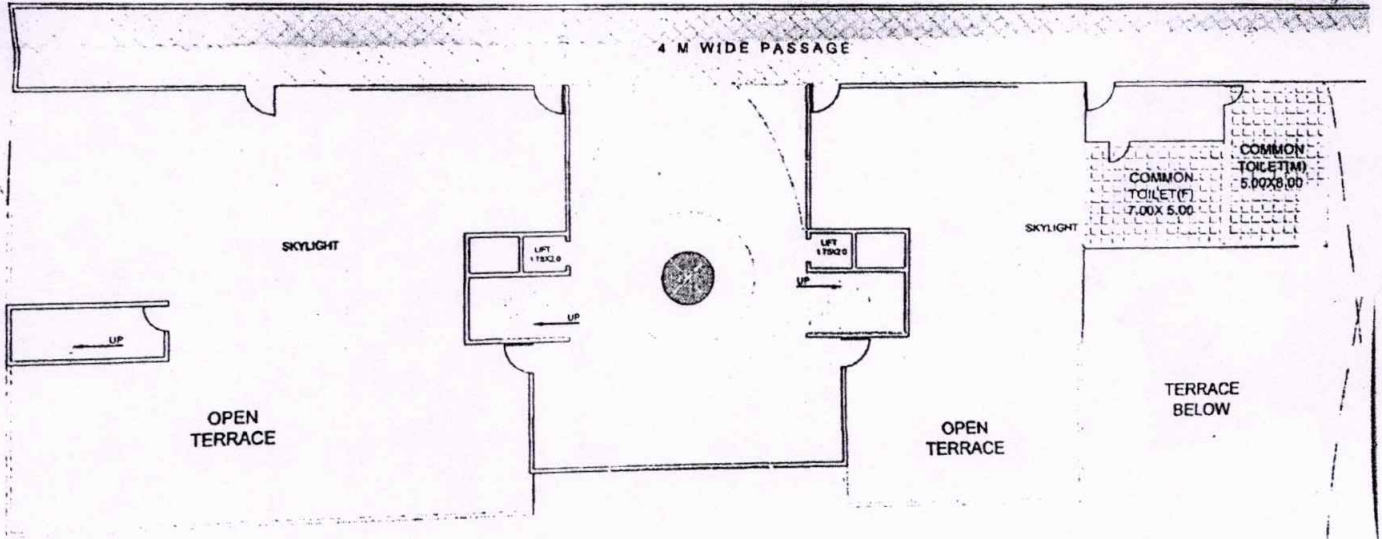


TERRACE
BELOW

POLY CARBONATE SHEET
(SKYLIGHT)

POLY CARBONATE SHEET
(SKYLIGHT)

OPEN
TERRACE



4 M WIDE PASSAGE

SKYLIGHT

OPEN
TERRACE

LIFT
11822.0

UP

LIFT
11822.0

UP

SKYLIGHT

OPEN
TERRACE

TERRACE
BELOW

COMMON
TOILET (M)
5.00x5.00

COMMON
TOILET (F)
7.00x5.00

SECOND FLOOR PLAN BUILT UP AREA=1661.0SQM

[Signature]
Sub Divisional Officer
P.W.D. (B/R)
5th Division Surajpur (C.G.)

[Signature]
Executive Engineer
P.W.D. (B/R) Division Surajpur
Distt. Surajpur (C.G.)



GOVERNMENT OF CHHATTISGARH

PUBLIC WORKS DEPARTMENT


**DETAIL ESTIMATE FOR CONSTRUCTION OF
DISTRICT COURT BUILDING AT SURAJPUR DISTT.
SURAJPUR(C.G.)**

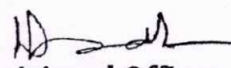
ESTIMATED COST - Rs. 3496.22 Lacs


**EXECUTIVE ENGINEER
P.W.D. (B/R) DIVISION
SURAJPUR (C.G.)**

GENERAL ABSTRACT
CONSTRUCTION DISTRICT COURT BUILDING AT SURAJPUR

S. No.	ITEM	AMOUNT	
1	2	3	
1	4		
1	Court Building	Upto Plinth Level	146213893.00
		Ground Floor	63747738.00
		First Floor	38289181.00
		Second Floor	11289341.00
		Total	259540153.00
2	Sanitary works & Water supply		2590012.00
3	Entrance Gate		1376002.00
4	Parking Shed		2253390.00
(A) TOTAL COST			265759557.00
5	Boundary wall		6787880.00
6	Landscaping		1625811.00
7	Cement Concrete Road		14031774.75
8	Nala Terraning work		3125863.13
9	FCA		5066582.00
(B) TOTAL COST			30637910.88
A	Add 12.00% for Internal Electrification		31891147.00
A	Add 3.50% for External Electrification		9301584.00
	Lift @1500000 (4 Nos)		6000000.00
(C) TOTAL COST			47192731.00
D=(A+B+C) TOTAL COST OF CIVIL WORK RS:-			343590198.88
D	Add 1.00% Work Charge & Contingency Rs:-		3435902.00
D	Add 1.00% Architectural & Structural Design Charges Rs:-		2595402.00
GRAND TOTAL RS:-			349621502.88
SAY RS:-			3496.22 LACS


Sub Engineer
PWD (B/R)
Sub Division Surajpur


Sub Divisional Officer
PWD (B/R)
Sub Division Surajpur


Executive Engineer
PWD (B/R)
Division Surajpur

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर (छ.ग.)

Phone No. (07775)-266992 (O)

E-mail Id -dfosurajpur@gmail.com

क्रमांक / मा.चि. / 638

सूरजपुर, दिनांक / 27 / 03 / 2026

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध)
अटल नगर नवा रायपुर छत्तीसगढ़

विषय:- Diversion of 1.82 ha Forest land in favour of PWD B and R Division Surajpur for Construction of New District Court Building, under Forest Conservation Act, 1980 at Surajpur District, in the State of Chhattisgarh-reg
पंजीयन क्रमांक **FP/CG/Others/152258/2022**

- संदर्भ:- 1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय अरण्य भवन, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक FC-I/IROCH-15/2022/963 दिनांक 12.10.2022
2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक / मा.चि. / 581 दिनांक 17.03.2026

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सूरजपुर के द्वारा प्रस्तावित नवीन जिला कोर्ट भवन निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित राजस्व वनभूमि खसरा क्रमांक 529 कुल रकबा 6.394 हे० में से 1.82 हे० राजस्व वनभूमि के व्यपवर्तन प्रस्ताव की प्रथम चरण की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा जारी की गई है। संदर्भित पत्र क्रमांक- 02 में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर को प्रेषित किया गया है। अधिरोपित शर्त क्रमांक-ii (b) **The Proposed non-forest CA land shall be transferred and mutated in favour of the State Forest Department before Stage-II Clearance** के परिपालन में आवेदक संस्थान के द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित राजस्व वनभूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। कार्यालय कलेक्टर जिला सूरजपुर का अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ खसरा पांचसाला पी-II की प्रति संलग्न है।

उक्त प्रकरण में प्रथम चरण की स्वीकृति के अधिरोपित शर्त क्रमांक-ii (b) के पालन प्रतिवेदन की जानकारी आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


वनमण्डलाधिकारी

सूरजपुर वनमण्डल, सूरजपुर

सूरजपुर, दिनांक / 27 / 03 / 2026

पू.क्रमांक / मा.चि. / 639

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
2. आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सूरजपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


वनमण्डलाधिकारी

सूरजपुर वनमण्डल, सूरजपुर

कार्यालय कलेक्टर | जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

क्रमांक/ 154169A
प्रति,

सूरजपुर, दिनांक 01.10.2019

कार्यपालन अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
सभाग सूरजपुर (छ.ग.)

विषय:- सूरजपुर जिले में प्रस्तावित जिला कोर्ट भवन निर्माण में प्रभावित वन भूमि के
संदर्भ:- उपरोक्त क्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भूमि आवंटित करने बाबत।
आपका पत्र क्रमांक 1382/तक./2019 सूरजपुर, दिनांक 31.7.2019 एवं इस
कार्यालय का पत्र क्रमांक/2251/वाचक/16 सूरजपुर, दिनांक 01.06.16.

---0---

संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा पांच वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव में ग्राम बकिरमा, तहसील-प्रेमनगर स्थित भूमि खसरा नंबर 780 रकबा 51.34 हे. में रो संयुक्त जिला कार्यालय भवन हेतु 4.046 हे. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित भूमि का चयन किया जाकर, वन विभाग द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपर्युक्तता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। उपरोक्त भूमि के चयनित रकबा 4.046 हे. में रो प्रस्तावित जिला कोर्ट भवन में प्रभावित 1.82 हे. राजस्व वनभूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव हेतु दुगुने 3.64 हे. क्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सूरजपुर के पत्र क्रमांक/1538/वाचक/2019 सूरजपुर, दिनांक 21.8.2019 के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम-बकिरमा, तहसील-प्रेमनगर स्थित भूमि खसरा नंबर 780 रकबा 51.34 हे. छोटे झाड़ के जंगल मद में दर्ज है। उक्त भूमि में से रकबा 4.05 हे. में तीन साल, दो तेन्दू, एक सीधा, दो महुआ के वृक्ष स्थित है। प्रस्तावित भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। आवंटित भूमि अटेम नदी के किनारे स्थित है। वृक्षारोपण हेतु उपर्युक्त है।

अतः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 01.06.2016 के माध्यम से प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की कंडिका 01 में उल्लेखित प्रयोजन में आंशिक संशोधन किया जाकर, जिला कोर्ट भवन सूरजपुर के निर्माण हेतु प्रभावित वन भूमि रकबा 1.82 हे. भूमि के एचज में ग्राम-बकिरमा, तहसील-प्रेमनगर स्थित भूमि खसरा नंबर 780 रकबा 51.34 हे. में से रकबा 3.64 हे. को वैकल्पिक वृक्षारोपण किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।


कलेक्टर

जिला-सूरजपुर

सूरजपुर, दिनांक 01/10/2019

पृष्ठांकन क्रमांक/ 154169A
प्रतिलिपि,

- वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- तहसीलदार प्रेमनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराये जा रहे उपरोक्त भूमि का सीमांकन कर वन विभाग को उपलब्ध कराकर, पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

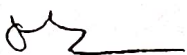

कलेक्टर

जिला-सूरजपुर

क्रमांक. 2427 नं डिने 14/10
प्रतिलिपि:- अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण (मं/सं.)

इस विभाग सूरजपुर/प्रेमनगर की ओर
सहायक कार्यपालक हेतु प्रेषित प्रस्ताव





कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. (म/स) सभाग सूरजपुर,
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)



फॉर्म पी-11 खसरा पांचसाला खण्ड-1 (श्रमिस्वामी का विवरण)

कृिष वर्ष: 2025-2026

ग्राम : बकिरमा (6406427)

हल्का : 00014

रा नि : प्रेमनगर

तहसील : प्रेमनगर

जिला : सूरजपुर

20260326640600006

श्रमि का ब्यौरा हेक्टयर में एवं करो का ब्यौरा रूपये पैसों में है ।

फॉर्म पी-11 खसरा पांचसाला खण्ड-1 (भूमिस्वामी का विवरण)

कृषि वर्ष: 2025-2026



ग्राम : बकिरमा (6406427)

हल्का : 00014

रा नि : प्रेमनगर

तहसील : प्रेमनगर

जिला : सूरजपुर

20260326640600006

भूमि का ब्योरा हेक्टेयर में एवं करो का ब्योरा रूपये पैसे में है।

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खाली में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	नाम	पिता या पति का नाम	जाति	निवास स्थान	पड़ती का क्षेत्रफल	अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई हो	किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार या किसी मौखी कास्तरकार के उपपट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिया गया भाग का क्षेत्रफल	कैफियत
780/3	3.6400 ()	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	पिता छ.ग.शासन		छ.ग.शासन		शासकीय भूमि		MD 202526640642700013 आदेश क्रमांक पूर्व पारित आदेश - FC-1/ROCH- 15/2022/963 / 10 Dec 2022 खसरा आईडी : 127427957 भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय अरण्य भवन नवा रायपुर के पत्र/आदेश क्रमांक FC-1/ROCH- 15/2022/963 दिनांक 12/10/2022

DGPS SURVEY BOUNDARY OF CA LAND AREA AGAINST COSTRUCTION OF SURAJPUR DISTRICT COURT BUILDING
 SUPERIMPOSED ON HIGH RESOLUTION SATELLITE IMAGE

VILLAGE - BAKIRMA, BLOCK - PREMNAGAR, DISTRICT - SURAJPUR, CHHATTISGARH

ANNEXURE-III



BASE STATION

DGPS SURVEYED AREA
 3.640 Hectare

INDEX

- BASE STATION
- BOUNDING POINTS
- DGPS SURVEYED BOUNDARY

DGPS Survey conducted & Map prepared by
 Mr. Nitendra Kumar Singh
 Chhattisgarh State Survey Office
 Vignani Bhawan, (C.O) P.O. Raipur

सर्वेक्षण प्रतिवेदन

350 (m)
 Surveyor

82°39'00"E

22°59'00"N 22°59'15"N 22°59'30"N